ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344
RNI : UPBIL/2016/67980
VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
Monthly / Bi-lingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking An Analisation

Peer Reviewed / Refereed Journal

Impact Factor
GIF = 0.543
Impact Factor
IIJIF = 6.134
Indexed with Google scholar
Impact Factor
SJIF = 5.879

ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	लोकपाल सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य : एक अध्ययन अंजना खेर, उज्जैन, म.प्र.	1-6
2	ई गवर्नेंस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ नसरल्ला गनवीर एवं आबेदा बेगम, राजनांदगांव	7-8
3	भारतीय राजनीति के समक्ष साम्प्रदायिकता की चुनौती, कारण एवं समाधान कल्लन सिंह मीना, गंगापुर सिटी, राजस्थान	9-13
4	प्राचीन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में गणतन्त्रात्मक व्यवस्था का विकास कविता देवी, मोर माजरा, करनाल	14-16
5	नरेश मेहता के काव्य में भाव–बोध शशि बाला रावत, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	17-18
6	अनसुलझे सवालों से जूझता उपन्यास 'एक इंच मुस्कान' मीना कुमारी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	19-21
7	माधवी : स्त्री जीवन की त्रासदी हबीब खान, डीडवाना, राजस्थान	22-25
8	मोहन राकेश के नाटकों में पारिवारिक बिखराव किरन लता दुबे, पश्चिम बंगाल	26-29
9	'दस बरस का भँवर' उपन्यास में मनोविकृति स्किजोफ्रेनिया की अभिव्यक्ति सुरिन्दर कौर, श्री मुक्तसर साहिब	30-33
10	हिन्दी स्तंभ–लेखन की परंपरा और हरिशंकर परसाई दीप नारायण चौहान, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	34-36
11	प्रभा खेतान की कृतियों में 'स्त्री–विमर्श' (बाजार के बीचः बाजार के खिलाफ भूमण्डलीकरण और स्त्री के प्रश्न के संदर्भ विशेष में) रामयज्ञ मौर्य, मेरठ	37-39
12	प्रेमचंद के उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार का चित्र अरुण कुमार साह, खान्दा	40-41
13	अस्मिता तलाशती नारी सन्दीपना शर्मा, जालन्धर	42-44
14	राधेमोहन राय के कहानी–साहित्य में प्रकृति चित्रण नरेश कुमार सिहाग, चेन्नई	45-47
15	दलित विमर्श सुशीला, भिवानी, हरियाणा	48-50
16	डॉ० श्याम सिंह शशि और यायावर साहित्य शक्ति शर्मा, उत्तराखण्ड	51-59
17	जनमानस की कवयित्री – मीरां सोहनराम, अजमेर	60-62
18	मध्यकालीन सन्त :– एक सामाजिक परिचय अरविन्द सिंह चौहान, अजमेर	63-65
19	हिन्दी साहित्य में स्त्री–विमर्श की भूमिका वीरेन्द्र भारद्वाज एवं अशोक कुमार मीणा, दिल्ली	66-68
20	संस्कृत वाङ्मय में नाट्यशास्त्र की उपयोगिता माधवी शर्मा एवं संजय मेहरा, खेरली, अलवर	69-70
21	कल्हण की ऐतिहासिक दृष्टि–कश्मीर के आलोक में अनिता सेनगुप्ता, इलाहाबाद	71-73

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation

ई गवर्नेस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र ई गवर्नेस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियों पर आधारित है। ई गवर्नेन्स का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शिता पूर्ण ढंग से शीघ्र कार्य का निर्माण करना है। इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाओं और योजनाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसे ही ई गवर्नेस, ई सरकार या डिजिटल सरकार के नाम से जानते हैं। ई गवर्नेस के द्वारा नागरिकों और व्यापारियों को सरल सुगम और महत्वपूर्ण योजनाये प्राप्त होती है। ई गवर्नेस के द्वारा अनेक योजनायें बनाई गई है जैसे–ई सेवा, ई नागरिक सेवा, ई चौपाल, ई बुक, ई पोस्ट पेमेंट बैंक इत्यादि।

मुख्य शब्द : ई गवर्नेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगॉव

आबेदा बेगम
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.कमला देवी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
राजनांदगॉव

प्रस्तावना

ई गवर्नेस को इलेक्ट्रानिक गवर्नेस, डिजिटल सरकार या ऑनलाइन सरकार के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के जरिए सरकारी सूचनाओं एवं सुविधाओ को आम जनता तक पहुँचाना ही ई गवर्नेस है। आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने यह तर्क संगत कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर. एण्ड पी.जी.) द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) का प्रारंभ किया गया। केन्द्र सरकार ने 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ एन.ईजी.पी. का अनुमोदन किया।

भारत में 1987 से निकनेट (उपग्रह आधारित कम्प्यूटर नेटवर्क) ई–प्रशासन पर मुख्य बल दिया गया, बाद में सभी जिलो कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण करने राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र की सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई। 1990 में राज्य की राजधानियों से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक इंटरनेट से जोड़ा गया। स्त्रोत india.govt.in

ई गवर्नेस को सरकार के द्वारा लोगों के हित के लिए बनाया गया है। जिसका मूल मंत्र है – "एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिये।"

अध्ययन का उद्देश्य

आम आदमी को ई गवर्नेस का अधिक से अधिक उपयोग करने व काम को शीघ्र करने, भ्रष्टाचार से मुक्त रहने की जानकारी तथा आम जनता को डिजिटल सेवा से परिचित करना।

ई गवर्नेस के लाभ या उपयोगिता

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिको, व्यापारियों और समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रहे है। अब लोगो को सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे सारा काम आसानी से कर सकते है। उदा. बैंक मे खाता खुलवाना, पैसा जमा करना, सभी तरह के बिल भुगतान (बिजली बिल, पानी का बिल, टैक्स इत्यादि) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

सभी तरह की टिकट बुकिंग, एयर, रेल्वे, बस, टैक्सी, होटल, इत्यादि। सभी तरह की खरीदी ऑन लाइन शॉपिंग के द्वारा की जा रही है। पेमेंट–क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटियम से कर सकते है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य लेन देन सभी ऑन लाइन हो गया है। नौकरी के लिए आवेदन, विद्यार्थी ऑन लाइन प्रवेश हेतु फार्म, रिजल्ट सब घर बैठे कर सकते है।

ई गवर्नेन्स का उद्देश्य

1. भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था मे बदलना।
2. भ्रष्टाचार कम करना।
3. सरकारी कार्यों मे गति लाना।
4. आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना, शीघ्र सरल सुविधा देना।

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

5. जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता लाना।
6. आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना।
7. पर्यावरण के लिए लाभदायक।
8. जवाबदेही निश्चित करना।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गांवो और पंचायतो तक ई क्रांति का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेस योजना के तहत इन्दिरा आवास, मनरेगा, समेत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धित योजनाओं का लाभ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। शहरों से गांवो की दूरी कम करने, सभी तरह के केन्द्र राज्य सरकार की सूचना देने सभी गांवो की पंचायतों का ब्राडबैंड से जोड़ने कहा गया है। सरकार ने जनता से संपर्क करने एवं कार्यो को सरल बनाने के लिये ई गवर्नेन्स की कुछ श्रेणियाँ बनायी है, जिससे आम नागरिको को लाभ हो रहा है। इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्य सरकारो से सीधा संपर्क कर रही है और राज्यों के कार्यो व गतिविधियों के बारे में जानकारी ले रही है।

ई गवर्नेन्स की श्रेणियाँ

- जी 2 जी सरकार से सरकार
- जी2सी सरकार से नागरिक
- जी2बी सरकार से व्यवसाय
- जी 2ई सरकार से कर्मचारी

जी.टू.जी.(सरकार से सरकार तक)

इसके माध्यम से ई गवर्नेस में एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। उदाहरण–किसी अपराधी के बारे में राज्य पुलिस विभाग को जानकारी मिली है तो वह संपूर्ण जानकारी सिस्टम में डाल देता है। उस अपराधी के बारे में देश के हर पुलिस स्टेशन में यह रिकार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे अपराधी को कहीं भी पकड़े में आसानी होती है।

इसी प्रकार भारत सरकार राज्य सरकारो को कोई जानकारी देना चाहे तो वेबसाइट पर जानकारी डाल देती है। सभी राज्य सरकार सूचना प्राप्त कर लाभ उठती है।

जी.टू.सी.(सरकार से नागरिक तक)

एक आम नागरिक इसकी सहायता से अपने सरकारी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। उदाहरण– बीमा पालिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकता है। जी.पी.एफ., ई.पी.एफ. सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

जी.टू.बी.(सरकार से व्यवसाय तक)

व्यापारी वर्ग को ई गवर्नेन्स की सुविधा प्राप्त है। वह घर बैठे कई सरकारी कार्यों को आसानी से कर सकता है जैसे– ट्रेडिंग, लाइसेंस के लिये आवेदन वैट के लिए पंजीकरण इत्यादि।

जी.टू.ई.(सरकार से कर्मचारी तक)

इसमें सरकार सरकारी कर्मचारी से आसानी से संपर्क कर सकती है। सरकार को किसी भी विभाग से जुड़े कर्मचारी की जानकारी उस विभाग के वेबसाइट के जरिये आसानी से प्राप्त हो सकती है। यह सरकार और कर्मचारी के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क करती है।

सी.टू.सी.(नागरिक से नागरिक तक)

इस प्रकार की ई सेवा में नागरिको का पारस्परिक संपर्क होता है। इन श्रेणियों का विकास कर सरकार, ई सेवा के माध्यम से एक ओर–प्रशासन को सशक्त, प्रभावशाली, पारदर्शी बना कर देश के आर्थिक सामाजिक विकास को द्रुत गति से आगे ले जाना चाहती है, वही दूसरी ओर आम जनता के जीवन को ई सेवा से सरल व सुगम बनाना चाहती है। यह देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ई गवर्नेन्स की चुनौतियाँ

ई गवर्नेन्स सरकारी काम काज को गति प्रदान करने का बहुत सरल सुगम तरीका है किन्तु इसे चलाने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है :–

1. वेबसाइट की हैकिंग।
2. इंटरनेट की सुविधा सही न होना।
3. फर्जीकाल द्वारा खाते से पैसा निकालना।
4. आधारकार्ड का बचत खाते से जोड़ने से जानकारी लिक होने का डर।
5. गाँवो में अशिक्षा, इलेक्ट्रानिक उपकरण का ज्ञान न होना।
6. गरीबी के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न होना (उदाहरण– मोबाईल, कम्प्यूटर नेट इत्यादि)।
7. सूचना क्रांति का ग्रामीण निर्धनों पर अल्प प्रभाव।

निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी को जनसाधारण तक पहुंचाने, योजनाओं को शीघ्र लागू करने, दस्तावेजों को सुव्यवस्थित साफ्टवेयर में रखने, गांवो से शहरो की दूरी मिटाने में ई गवर्नेस एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सेवा है। इसमें सरकार व जनता दोनो सक्रिय रूप से भागीदारी होना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में जहां ई–गवर्नेस से बहुत लाभ हो रहा है वही कुछ समस्यायें चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होते दिख रहा है परन्तु अपराधों पर नियंत्रण लाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जनता को सचेत हो कर सभी कार्य करने की जरूरत है। सरकार की सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *योजना नवम्बर 2013 – पृ. 31–34*
2. *डॉ. फड़िया बी.एल. , लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा 2009 पृ. 950*
3. *योजना नवम्बर 2014 डिजिटल डेमोक्रेसी*
4. *मिश्र उमाशंकर – डिजिटल डेमोक्रेसी और पत्रकार योजना नवम्बर 2014*
5. *राष्ट्रीय पोर्टल–20, इंटरनेट से प्राप्त आंकड़े*

Peer Reviewed
ISSN (P) : 2321-290X * (E) 2349-980X
RNI No. : UPBIL/2013/55327

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Peer Reviewed / Refereed Journal

VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.689
GIF = 0.543
IIJIF = 6.038

UGC S.NO. 40880
Shrinkhla UGC Approved

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala
शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

20	**'Women Short –Story Writers of Assam': A Golden Bond of Friendship with the Neighbouring Literature** Agnimitra Panda, Bolpur, West Bengal	92-93
21	**कानपुर नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा में महिला शिक्षिकाओं का योगदान** ममता शुक्ला, दिबियापुर, औरैया	94-96
22	**प्राचीन एवम् आधुनिक राम काव्य में 'स्त्री विमर्श'** सन्दीपना शर्मा, जालन्धर	97-100
23	**हिंदी नाटकों में स्त्री अस्मिता का प्रश्न** राज भारद्वाज एवं अशोक कुमार मीणा, दिल्ली	101-104
24	**विकास का दंश झेलती कोयलांचल की महिलाएं** मीना कुमारी, रानीगंज, पश्चिम बर्दवान, पश्चिम बंगाल	105-110
25	**"रिसते रिश्ते" उपन्यास : एक अध्ययन** रूबी जुत्शी, श्रीनगर	111-115
26	**शिक्षा – आज के सन्दर्भ में** नीतू गुप्ता, कानपुर	116-118
27	**सामन्तवादी मानसिकता के खिलाफ मीरा का विद्रोह : एक जन चेतना** सोहनराम, राजस्थान	119-121
28	**मध्यकालीन संतों के काव्यों में सामाजिक चेतना का अध्ययन (राजस्थान के सन्तों के सन्दर्भ में)** अरविन्द सिंह चौहान, राजस्थान	122-127
29	**भूमण्डलीकरण और सांस्कृतिक अस्मिता** हबीब खान, डीडवाना	128-133
30	**आधुनिकता की दौड़ में संस्कृत की उपेक्षा किन्तु समृद्ध भविष्य** मधुबाला मीना, अलवर	134-138
31	**भक्ति का दार्शनिक चिन्तन–पाञ्चरात्रागम के आलोक में** अनिता सेनगुप्ता, इलाहाबाद	139-141
32	**शब्द भावों से परे शख्सियत – डॉ. मधु भट्ट तैलंग** मैनेजर लाल बैरवा, जयपुर	142-149
33	**राव कलाकारों का संगीत शिक्षण में योगदान** संजय कुमार बारेठ, जयपुर	150-153
34	**मेवाड़ लघुचित्र शैली एवं उसमें अश्वों का कलात्मक अंकन** मनीषा खींची एवं इशरत उल्लाह खान, जयपुर, राजस्थान	154-157
35	**राजस्थान में पर्यावरण पर्यटन–समीक्षात्मक अध्ययन (मरू जिला–बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में)** श्रवण कुमार प्रजापत, बीकानेर, राजस्थान एवं संजीव बंसल, नेहर, राजस्थान	158-160
36	**उत्तराखण्ड में औद्योगिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन–सूक्ष्म व लघु उद्योग के संदर्भ में** मंजु जोशी, अरुणाचल प्रदेश	161-163
37	**प्लास्टिक प्रदूषण समस्या एवं समाधान** नागरत्ना गनवीर एवं आबेदा बेगम, राजनांदगांव	164-166
38	**नागरिक अधिकार एवं भारतीय परिदृश्य** कविता देवी, मोर माजरा, करनाल	167-171
39	**सशक्त भारतीय विदेश नीति के लिए मालदीव में शांति जरूरी** प्रभप्रीत सिंह, चण्डीगढ़ एवं स्वाती सोम, हरियाणा	172-175
40	**पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका** मुकेश कुमार बगड़िया, जयपुर	176-180

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्लास्टिक प्रदूषण समस्या एवं समाधान

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव

आबेदा बेगम
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.कमला देवी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
राजनांदगांव

सारांश

धरती का अस्तित्व खतरे में डालने वाला यह सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। यूज एण्ड थ्रो के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग आसानी से करता है किन्तु प्लास्टिक पुरी दुनिया के लिए "परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक है।" प्लास्टिक 100 साल तक नष्ट नहीं होता है। यह नालियों में गिरता है तो नालियाँ चोक (जाम/बंद) कर देता है और जमीन में गिरने से जमीन को बंजर बना देता है। यह मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षियो, समुद्री जीवों, पेड़ पौधो एवं संपूर्ण पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरनाक है। सरकार प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने अनेक कानून बना रही है किन्तु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना बंद नहीं कर पा रहा है। प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक संभव नहीं है लेकिन नागरिको की भी पर्यावरण के प्रति कुछ खास जिम्मेदारी है जिन्हें वे समझदारी से उपयोग करे तो इसके खतरो से काफी हद तक बच सकते है।

मुख्य शब्द : प्लास्टिक प्रदुषण समस्या एवं समाधान।

प्रस्तावना

तकरीबन नब्बे साल पहले हमारे जीवन में प्लास्टिक का नामोनिशान नहीं था, पर अब पूरी दुनिया में इसने अपने पाँव पसार लिये है। आज जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो प्लास्टिक से अछूता है। घर के सभी सामान जैसे – बच्चो के खिलौने से लेकर हवाई जहाज तक अर्थात् खाने पीने के लंच बाक्स, दूध, पानी की बोतले, पेन, पेंसिल, बैग, कपड़े, जूते, चप्पल, अलमारी, टेबल, चेयर, पलंग इत्यादि एवं इलेक्ट्रानिक चीजो में मोबाइल, टी.वी., लैपटाप, फ्रीज, वाशिंग मशीन, मोटर कार, हवाई जहाज इत्यादि सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। वास्तव में यह हमारे जीवन के लिए एक ओर सुविधा जनक है तो दूसरी ओर प्रदूषण फैला रहा है। संपूर्ण प्राणी जगत एवं प्रकृति के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अतः इसका इस्तेमाल कम से कम करने का हमे संकल्प लेना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्लास्टिक से होने वाले खतरे से आगाह करना।
2. प्लास्टिक का उपयोग जहाँ अत्यधिक जरूरी है वहीं करना (जैसे–इलेक्ट्रानिक्स चीजो में), सामान लाने ले जाने में न करना एवं प्लास्टिक में गरम खाने की चीजे न रखने के लिए जागरूकता बढ़ाना।
3. प्लास्टिक को कही भी फेंकने से रोकने के लिए जागरूकता लाना।
4. प्लास्टिक कचरे का उचित निस्तारण (उपयोग)

प्लास्टिक की शुरूआत ईसा पूर्व 1600 में प्राकृतिक रूप से रबर के पेड़ो से मिलने वाले रबर माइक्रोसेल्यूलोज, कोलेजन और गैलाइट के मिश्रण से गेंद (बाल), बैंड और मूर्तियाँ बनाने में किया गया किन्तु आधुनिक प्लास्टिक का श्रेय ब्रिटेन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स को जाता है जिन्होंने प्लास्टिक का उपयोग सजावटी समान बनाने में हाथी दांत जैसा दांत बनाने के लिए किया। इनका उद्देश्य हाथियों की हत्या को रोकना था। उन्होंने 1856 बर्मिंघम में इसका पेटेंट भी करवाया। लेकिन यह किस्म अत्यधिक लचीली नहीं थी। सन् 1900 में प्लास्टिक क्रांति आई जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह सिंथेटिक रूप में सामने आया।[1]

सच्चे प्लास्टिक बनाने का श्रेय 1907 में बेल्जियम मूल के अमरीकी वैज्ञानिक लियो एस.बैकलैंड को जाता है। उन्होंने कहा था "अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा यह अविष्कार (बैकेलाइट) एक नये भविष्य की रचना करेगा।" ऐसा हुआ भी इसीलिए टाइम्स मैग्जीन ने अपने कवर पेज में बैकलैंड की तस्वीर छापी और लिखा–"ये न जलेगा ना पिघलेगा"। 2 वास्तव में बैकलैंड इलेक्ट्रिक मोटरो और जेनरेटरों में तारों की कोटिंग के लिए एक पदार्थ की खोज कर रहे थे जो गोंद जैसा चिपचिपा हो और सूखने पर पपड़ी या सख्त हो जाता हो।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

इनका प्रयोग सफल रहा और उन्होंने प्लास्टिक बनाने वाली कम्पनी का पेटेंट हासिल कर लिया। प्लास्टिक का आणविक भार अत्यधिक होता है। इसी कारण यह किसी भी वातावरण में खराब नहीं होता है। अत्यधिक सुविधाजनक यह प्लास्टिक दूध, दवा, पानी, तेल से लेकर सब चीजो के लाने लेजाने (सुरक्षित) रखने में हमारे घर, दुकान, ऑफीस सर्वत्र घुसपैठ कर चुका है। आज हमारी दिनचर्या में इतनी अधिक प्लास्टिक की चीजें उपयोग मे लायी जाती हैं कि अगर किसी दिन इनका उपयोग न किया जाए तो शायद दुनिया अधूरी लगेगी। हम अंधाधुंध प्लास्टिक का इस्तेमाल कर पर्यावरण को इतने गंभीर खतरे में डालते जा रहे हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। हर साल दुनिया में पाँच सौ अरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। हर मिनट में दस लाख से ज्यादा बैग इस्तेमाल कर फेंक दिए जाते हैं।[5] पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 88 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है। इसी कारण समुद्री जीव हर साल अत्यधिक संख्या में दम तोड़ रहे है।[4]

1960 के दशक की तुलना में आज 20 गुना अधिक प्लास्टिक बन रहा है। जिस तेजी से प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है अगर ऐसी ही स्थिति रही तो 2050 तक 33 अरब टन प्लास्टिक और बना चुके होंगे जिसका बड़ा हिस्सा महासागरो मे पहुंच जायेगा और सदियों तक वहीं बना रहेगा। अगर वर्तमान में समुद्रों में पड़े प्लास्टिक कचरे को साफ करने की बात करे तो जिस रफ्तार से काम चल रहा है करीब 800 साल लग जायेंगे।[5] प्लास्टिक के कारण 1200 से ज्यादा समुद्री जीवो की प्रजातियाँ खतरे में है।

हम जिस प्लास्टिक का उपयोग करते है उसमें 50 फीसदी सिंगल यूज या डिस्पोजेबल प्लास्टिक है। इसमें पानी की बॉटल, चम्मच, कटोरी, प्लेट ग्लास जैसी चीजे हैं। हर मिनट में 10 लाख पानी की प्लास्टिक बोतले खरीदी और पीकर फेकी जा रही हैं। 2017 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक अनुमान में बताया कि भारत में प्रतिवर्ष करीब 25,940 टन प्लास्टिक बनाया जा रहा है।[6]

भारत में पहले थैले या बैग लेकर लोग मार्केट जाते थे किन्तु अब थैला या बैग ले जाना प्रेस्टीज ईसू बनते जा रहा है। आज कोई भी शहरी व्यक्ति सामान लेने जाता है तो सामान लाने के लिए कोई तैयारी कर के नहीं जाता। चाहे जितना सामान लाना है सब्जी, फल, कपड़ा, बर्तन, सब पॉलिथीन में भर कर लाते है और फिर उसे खाली कर फेंक देते हैं। प्लास्टिक का उपयोग आसान और सस्ता होने के कारण इसका इस्तेमाल क्रेता और विक्रेता दोनो कर रहे हैं।

करीब सौ सवा सौ साल की प्लास्टिक की यात्रा ने पिछले 40–50 वर्षों में सबसे ज्यादा तरक्की की है। 1950 से प्लास्टिक का चलन तेजी से बढ़ा है। करीब 20 लाख टन से 40 टन करोड़ प्रोडक्ट हमारे जीवन मे घुसपैठ कर चुके है।

प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। प्लास्टिक चूँकि सालो खराब नहीं होता है साथ ही विद्युत का कुचालक है, पिघलने पर मन चाही आकृति में ढाल कर सामान बनाये जाते है, अतः इसका उपयोग बहुतायत से होता है। टूटने फूटने का भी डर नहीं है, हर चीज सुरक्षित हो जाती है आज के युग को प्लास्टिक संस्कृति का युग कहे तो भी कोई अतिसंयोक्ति नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ 85 प्रतिशत पैकिंग प्लास्टिक में कर रहीं है जिसमें कवर से लेकर रस्सी तक उसी की होती है।

प्लास्टिक पुस्तक की लेखिका सुजैन फ्रीनकेल लिखती है कि हम एक दिन की दिनचर्या में 24 घण्टे में 196 प्लास्टीक की चीजो का इस्तेमाल करते हैं जबकि गैर प्लास्टिक चीजो की संख्या 102 रहती है।[7] प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। यह सुविधा जनक है किन्तु उपयोग के बाद जब फेंका जाता है तो सब जगह विषैला हो जाता है। धरती पर पड़ने से धरती बंजर हो जाती है और नालियों में पड़ने से नालियाँ जाम। जानवरों के खाने से जानवर तड़प कर मर रहे हैं, समुद्री जीव खतरे में है। भारत में प्रतिदिन 20 गायें पॉलिथीन खाने से मर रही है। प्रतिवर्ष मुंबई शहर में पानी ही पानी भरने का एक मात्र कारण नालियों का प्लास्टिक से जाम होना है। विशेषकर मुंबई में 1998 में भयंकर बाढ़ का एक मात्र कारण नालियों में पालिथीन का जाम होना था। इस प्रकार भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्लास्टिक एक गंभीर समस्या बनते जा रहा है। भारत में प्लास्टिक बनाने में 30 हजार से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई है।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत में 60 शहर रोजाना 3500 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई कलकत्ता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकाला जा रहा है।[8] भारत में 80 प्रतिशत प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है।

प्लास्टिक से खतरा क्या है? –

1. प्लास्टिक व पालिथीन दोनो मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
2. प्लास्टिक के डिब्बों में गरम खाना रखने से स्तन कैंसर और भ्रूण संबंधी गंभीर बीमारियाँ हो रही है साथ ही दमा/अल्जाइमर का खतरा बढ़ रहा है।
3. प्लास्टिक की बोतलो में पाया जाने वाला खास तत्व थैलेटस की वजह से हॉर्मोनो का रिसाव करने वाली ग्रंथियों का क्रियाकलाप बिगड़ जाता है।(9)
4. जानवरो के पेट फूलने व मरने का एक बड़ा कारण उनका प्लास्टिक की थैलियों में रखा खाद्य पदार्थ खाना है, वे थैलियों सहित खा लेते है। अहमदाबाद में 100 किलोग्राम कचरा एक गाय के पेट से निकाला गया जिसमें ज्यादा पॉलिथीन की थैलियाँ थी।(10)
5. गिर के जंगल में शेर के पेट से भी पॉलिथीन की थैलियाँ निकाली गई जो बहुत खतरनाक है।
6. अकेला अमेरिका प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों में हर साल 340 अरब डालर खर्च कर रहा है।
7. प्लास्टिक सौ वर्ष तक नष्ट नहीं होता और इसे जलाने से विषैली गैसो से ओजोन परत को नुकसान होता है।

8. उत्पादन से इस्तेमाल तक तथा बाद में (कचरा) सभी अवस्था में समुचे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरनाक है।
9. प्लास्टिक की वजह से हर साल एक लाख समुद्री जीव मर रहे है।
10. वाटर रीचार्जिंग में बाधक।
11. 40% नाले, नालियाँ, नल, पॉलिथीन के कारण जाम हो रहे हैं।
12. नालियों के जाम होने से मच्छर, वायरस, डेंगू, मलेरिया और पीलियाँ जैसी संक्रमक बीमारियाँ हो रही हैं। छ.ग. के भिलाई शहर में (दो माह में) 43 मौते डेंगू से हुई है।
13. हर साल देश में 56 लाख टन प्लास्टिक के कचरे का नया पहाड़ खड़ा हो रहा है। (11)

सरकारी प्रयास

खतरनाक प्लास्टिक पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए अनेक कानून बनाये है किन्तु प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में सिंगल यूज वाला प्लास्टिक का हर सामान बैन किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने अनेक कानून बनाये हैं–

1. इस्तेमाल किए जाने वाली प्लास्टिक के उत्पादन और प्लास्टिक की मोटाई की जानकारी थैली पर छापना होगा।
2. दुकानदारों को खुली थैलियों में सामान बेचने पर पाबंदी है।
3. दुकानदारों को "वापस खरीदो" योजना के तहत ग्राहकों से पैकेजिंग में बेचे गये सामान की थैली वापस खरीदनी होगी।

प्लास्टिक बैग, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक कटलरी और थर्मोकोल के समान पर प्रतिबंध होगा।

सुझाव

1. प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल से बचना चाहिए।
2. गरम चीजें जैसे खाना, दूध, पानी, चाय, प्लास्टिक में न रखें।
3. प्लास्टिक की रिसाइकलिंगि को बढ़ावा देना चाहिए।
4. जवाबदेही तय होना चाहिए।
5. पालिथीन का उपयोग बंद करने में महिलाओं का सहारा लिया जा सकता है। वे संकल्प ले तो काफी हद तक पालिथीन प्रतिबंधित करने में कामयाब हो सकते है।
6. सभी जगह पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। लोगो को कपड़े या पेपर के बैग का उपयोग करे।
7. पालिथीन के कचरे से सड़क बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। सड़के मजबूत होगी।
8. मकानो केनिर्माण कार्य में रेत (बालू) की जगह प्लास्टिक का आंशिक रुप से उपयोग किया जाये।
9. मनुष्य को स्वयं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। पर्यावरण हमारी आवश्यकता है, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी मनुष्य स्वस्थ रहेगा इसे समझने की जरूरत है।
10. प्रतिबंधित पालिथीन का उपयोग करने वालो के लिए दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। पालिथीन कहीं भी फेंका न जाये इस पर भी कानून बनना चाहिए।

केन्द सरकार, राज्य सरकार, व्यापारिक संगठनो एवं आम नागरिक को संकल्पबद्ध होकर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। धरती का श्रृंगार हमारे पेड़ पौधे, जीव जन्तु, समुद्र, नदी, नाले सभी स्वच्छ रखने होंगे। जिस तरह पालिथीन का उपयोग हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाको में बैन है वैसे ही भारत में सभी जगह होना चाहिए। हिमाचल में पालिथीन में कोई सामान नहीं मिलता है। सरकार द्वारा बोर्ड लगाये गये है जो भी पॉलिथीन फेकते पाया गया उसे 5000 रूपये जुर्माना है। प्रत्येक टैक्सी या कार में डस्टबीन रखना आवश्यक है वरना तुरन्त फाईन देना पड़ता है। अतः पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनो को स्वस्थ रखना है तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। इसके लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। स्वयं में सुधार लाने की जरूरत है तभी हम शुद्ध सांस ले पायेगें वरना वो दिन दूर नहीं जब मुंह पर मास्क और पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेण्डर ले कर चलना होगा। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2018 मनाया गया इसका विषय था "प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएँ" इसमें सरकारों, उद्योगो और जनसमुदाय से आग्रह किया गया था कि वे प्लास्टिक से नाता तोड़े क्योंकि प्लास्टिक परमाणु बम है जिससे पृथ्वी को बचाना है मानव जगत को बचाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *विज्ञान प्रगति/पर्यावरण विशेषांक/जून 2018/पृ.10*
2. *वही पृ.11*
3. *दैनिक भास्कर/पर्यावरण दिवस विशेष/5 जून 2017*
4. *विज्ञान प्रगति/प्लास्टिक से कराहते महासागर/जून 2018/पृ.97*
5. *दैनिक भास्कर/5 जून 2017*
6. *दैनिक भास्कर/एम.वैंकया नायडू उपराष्ट्रपति/24 अप्रैल 2018*
7. *विज्ञान प्रगति/जून 2018/पृष्ट 12*
8. *वही/पृष्ट–14*
9. *विज्ञान–प्रगति/जून 2018/पृ.15*
10. *वही पृ.13*
11. *दैनिक भास्कर/5 जून 2017*

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-3* June - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन की संभावनाएं

Chances of Milk Production in Chhattisgarh State

Paper Submission: 10/06/2020, Date of Acceptance: 20/06/2020, Date of Publication: 25/06/2020

सारांश

राज्य में पशुधन का उत्पादन लगातार बढते जा रहा है । वर्ष 2019 सितम्बर तक वार्षिक दुग्ध उत्पादन दर लगभग 7.6% हो गयी है । जो पूर्व वर्षो से लगभग 3.8% वार्षिक वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गयी है। इसका मुख्य कारण है राज्य में डेयरी उद्योग को राज्य शासन द्वारा लगातार बजटीय प्रावधानों का बढ़ाना एवं विशेष ध्यान दिया जाना है। राज्य में जितना दूध उत्पादन किया जाता है वह शहरों एवं जिला स्तर या तहसील स्तर पर उपभोग कर दिया जाता है केवल 5 लाख लीटर दूध बाजार में पहुँच पाता है।

Livestock production in the state is continuously increasing. By the year 2019 September, the annual milk production rate has been almost 7.06. Which has reached a national level of about 3.98% from previous years. The main reason for this is that the dairy industry in the state has to constantly increase budgetary provisions and special attention is given by the state government. The milk produced in the state is consumed at the cities and district level or tehsil level, only 5 lakh liters of milk can reach the market.

काव्या जैन
शोध छात्रा
शा.दिग्विजय स्वशासी
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

ए.एन.माखीजा
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शास.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

मुख्य शब्द : दुग्ध व्यवसाय , कृषि व्यवसाय , डेयरी व्यवसाय , परियोजनाएं पशु चिकित्सालय, गौपालन एवं गौशाला प्रबंधन ।
Milk Business, Agribusiness, Dairy Business, Projects Veterinary Hospital, Cow rearing and Cowshed Management

प्रस्तावना

भारत विश्व के अन्य दूध उत्पादक देशों में अग्रणी है आज हमारे देश में 79 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई उत्पादक पशुओं की संख्या एवं कृषि की आधुनिक पद्धति है कृषि के विकास से ही पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय की उन्नति संभव है। दुग्ध व्यवसाय एवं कृषि व्यवसाय एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है, यदि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है तो दुग्ध व्यवसाय को साथ में अपनाना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा देश की आर्थिक स्थिति में सुधार विषम परिस्थितियों जैसे अकाल, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवर्षा, आदि के समय हो सकता है तथा जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन बन सकता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए दुग्ध व्यवसाय वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन स्वरोजगार का सबसे कम लागत वाला व्यवसाय है। जो कि बेरोजगारी, भूखमरी, निर्धनता को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसलिए यदि छत्तीसगढ़ में धान आधारित फसल पद्धति के साथ दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए तो यहां के गौशालाओं, किसानों, ग्रामीण, बेरोजगार एवं पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. छ.ग.राज्य मे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना बनाना ।
2. राज्य में गोवंश एवं भैसवंशीय पशुओं की जनसंख्या तथा विकासक्रम का पता लगाना।
3. गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशाला का सुदृढ़ीकरण ।
4. पशु चिकित्सा एवं पशुओं के आहार की स्थिति का पता लगाना ।
5. राज्य में दुग्ध उत्पादन के उपभोग की दर ज्ञात करना ।

छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन की संभावनाएं

छ.ग. में डेयरी व्यवसाय के लिए अत्यधिक संभावनाएं है, क्योंकि यहां कि जलवायु व भौगोलिकता उपयुक्त है । इसका उचित उपयोग तब हो सकता है जब वैज्ञानिक परियोजना बनाई जाये। अभी तक जितनी भी योजनाएं बनी उनका उचित परिपालन नहीं हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश एक वृहद राज्य था जिनमें

परियोजनाओं का उचित लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पा रहा था। यह सौभाग्य की बात है कि हमें नया राज्य मिला एवं इसके बाद छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत सफलता मिली एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डेयरी व्यवसाय देश में सातवें स्थान पर हैं। इसका मुख्य कारण यह है राज्य सरकार द्वारा सन 2001 से 2019 तक 1.45 करोड़ की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की गई जिसमें डेयरी विकास को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा विकास हुआ है। साथ ही प्रदेश में दुग्ध महासंघ की स्थापना, गौसेवा आयोग एवं किसान कल्याण परिषद की स्थापना से पशु पालकों एवं कृषकों तथा दुग्ध व्यवसायियों को सामाजिक, आर्थिक उन्नति करने में उचित मदद प्राप्त हुई हैं। (पशुधन विकास की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 2001–2018) शासन द्वारा पशुधन विकास नीति तो बनाई गई परंतु प्रदेश की गौशाला एवं डेयरी के लिए उचित नीति नहीं बनाई गई। जिससे प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति अत्यंत कमजोर है वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर कृषि पर आधारित डेयरी विकास पर नई नीति बनाई जाए जिससे डेयरी व्यवसाय का उचित विकास हो सके साथ ही गौशालाओं का आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण किया जा सके।

छत्तीसगढ़ अंचल में धान फसल पद्धति ही अपनाई जाती है। लेकिन यह देखा गया है कि अन्य परंपरागत फसलों के उत्पादन मात्र से ही यहां के किसानों का आर्थिक उत्थान संभव नहीं हैं। क्योंकि इस अंचल में सिंचाई संसाधनों के अभाव में धान उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में दुग्ध उत्पादन यहां के किसानों की आमदनी का एक उपयुक्त साधन हो सकता है। क्योंकि धान की फसल के उप उत्पादों का उपयोग पशुधन के चारे के रूप में किया जा सकता है तथा पशुओं से प्राप्त गोबर गोमूत्र का उपयोग वर्तमान स्थिति में सबसे उपयुक्त खाद एवं गोमूत्र से कीट नियंत्रक बनाकर खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया जा सकता है।

इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नरवा, गरवा घुरवा एवं बाड़ी के रूप में एवं महत्वाकांक्षी शीर्षस्थ परियोजना को प्रदेश में शुरू किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन गौशाला स्तर पर ही एवं किसानों एवं गौशालाओं को आर्थिक आय से सुदृढ़ बनाना है धान आधारित फसलोत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है। जिसे अपनाकर इस अंचल के कृषकों एवं गौशालाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सबल बना सकते है। दुग्ध व्यवसाय को कृषि फसल पद्धति के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं पर आधारित डेयरी विकास नीति का निर्धारण किया जाए –

1. कृषि एवं डेयरी व्यवसाय सहकारिता कार्यक्रम ।
2. पशु पालन पर आधारित परियोजनाएं –
   जैसे–
a) प्रजनन पर आधारित परियोजनाएं ।
b) देशी नस्लों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना।
c) उन्नत किस्म के प्रजाति के जननद्रव्य का उत्पादन पर संकरीकरण।
d) चारा उत्पादन एवं पशु आहार प्रबंधन कार्यक्रम।
e) चलित पशु चिकित्सालय परियोजना।
f) पशु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
g) पशु प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन आदि।
3. दुग्ध उत्पादन एवं संसाधन पर अनुसंधान –
a) उचित पशु जाति का चयन।
b) पोषण प्रबंधन ।
c) फसलोत्पादन की परिस्थितियों की डेयरी व्यवसाय पर आधारित समन्वयक परियोजना
4. पशुपालकों एवं दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम ।
5. दूध संकलन एवं उचित मूल्य निर्धारण कार्यक्रम।
6. पुरानी दुग्ध उत्पादन तकनीकी का नवीनीकरण।
7. लघु स्तर पर स्थित संयंत्रों का निर्माण ।
8. गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम।
9. सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, भारवाही एवं चरवाही प्रथा की वैकल्पिक पद्धति की खोज।

प्रजनन नीति

गायों को वर्तमान प्रजनन नीति के अनुसार निश्चित नस्ल की गायों को दूध तथा बैलों को भारवाहन क्षमता के लिए अनुवांशिक आकलन के आधार पर विकसित किया जाता है। तथा बहुत कम दूध देने वाली नस्ल की देशी गायों का अधिक दूध देने वाली देशी नस्लों से संकरण कराके संकर गायों के अन्त प्रजनन द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। प्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि सन 2000 में 8 करोड़ टन दूध उत्पादन करना था। अच्छी नस्ल के बढ़िया सांड के वीर्य को संकलित कर उसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए वितरित करने की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा दुधारू पशुओं के लिए राष्ट्रीय समूह बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है यदि इसको सुचारु रूप से राज्य स्तर पर लागू किया जाए तो दूध उत्पादन और अधिक बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में लगभग **80%** देशी नस्ल है यदि उन्नत किस्म के सांडों का उपयोग कर हिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराया जाय तो छ.ग. में अन्य राज्यों की भांति दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

तालिका क्रमांक – 01

राज्य में प्रस्तावित गोवंश एवं भैंसों की जनसंख्या तथा विकास क्रम

(लाख में)

विवरण	10वीं योजना के अंत में (2006) (उपलब्ध)	11वीं योजना के अंत में (2011) (लक्षित)	12वीं योजना के अंत में (2012) (लक्षित)	13वीं योजना के अंत में (2021) (लक्षित)
गैर वर्णात्मक गोवंश	71.06	69.30	67.59	65.92
संकर (प्रजनन) पशु / सुधार	17.76	26.09	38.33	56.32

देशी नस्ल				
कुल गोवंश	88.82	95.39	105.92	122.24
गैर वर्णात्मक भैंस	14.36	14.01	13.6	13.31
वर्गीकृत भैंस	9.60	2.14	2.86	3.82
कुल भैंस	15.96	16.15	16.52	17.13

Source – पशु विभाग

1. गैर वर्णात्मक मवेशियों (सांडो) में लगभग 0.5% की वृद्धि हो जायेगी।
2. प्रजनित पशु/स्वदेशी सांडो में सालाना 0.6% की वृद्धि होगी।
3. गैर वर्गीकृत भैंसो में सालाना 0.5% की वृद्धि होगी।
4. वर्गीकृत भैंसो में सालाना 0.8% की वृद्धि हो जायेगी।

शंकर सांड उत्पादन कार्यक्रम

प्रारंभ में प्रचलित सांड उत्पन्न प्रजनन फार्म स्थापित किए गए तथा सांडों का चयन उनकी शारीरिक रचना तथा दूध की उत्पादन क्षमता के आधार पर ऐसे चयनित सांडों का उपयोग प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रजनन के लिए किया गया है। दसवी पंचवर्षीय योजनाओं में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों एवं कुछ विदेशी नस्लों के प्रजनन फार्म इन नस्लों सांडों का संतति परीक्षण करने के लिए स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम में 300 प्रजनन योग्य मादाओं पर 10 सांडों का संतति परीक्षण किया गया जिसमें 10 से 12 मादा संतति का आकार के आधार पर नहीं था।

संगठित गौशालाओं के सहयोग से उपलब्ध समूह द्वारा भी सांडो की वांछित संख्या उत्पन्न नहीं की जा सकती है इसलिए किसानों की प्रजनन योग्य गायों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करना होगा। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी द्वारा अनुवांशिक विकास में वृद्धि तथा पीढ़ी अंतराल कम किया जा सकता है। इससे प्रतिवर्ष लगभग दो से तीन प्रति लीटर तक दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एवं कुल ग्रोथ दर पंचवर्षीय योजना **2006** से **13**वीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग 6.5% की दर से दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

(Table - II)

तालिका क्रमांक – 02

विकासक्रम एवं लक्षित कार्य

विवरण	10वीं योजना के अंत में (2006) (उपलब्ध)	वर्तमान स्तर (2009)	11वीं योजना के अंत में (2011) (लक्षित)	12वीं योजना के अंत में (2016) (लक्षित)	13वीं योजना के अंत में (2021) (लक्षित)
दुग्ध उत्पादन (लाख/लीटर/दिन)	8.31	9.09	11.38	15.59	21.35
प्रति गोवंश द्वारा (ग्राम प्रतिदिन)	112	119	153	210	288
वार्षिक वृद्धि दर :	4.18	3.13	6.5	6.5	6.5

Source – पेरापेट प्रशिक्षण पुस्तिका

1. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2006 की 10वीं पंचवर्षीय योजना में दुग्ध का उत्पादन 8.31 लाख लीटर प्रति दिन था जो कि 2021 की 13वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़कर 21.35 लाख लीटर प्रतिदिन हो जायेगी।
2. प्रति मवेशी दुग्ध उत्पादन 112 ग्राम/दिन से बढ़कर 288 ग्राम/दिन हो जायेगी। (157%) की वृद्धि।
3. राष्ट्रीय : प्रति मवेशी दुग्ध उत्पादन 252 ग्राम प्रतिदिन।

चारा उत्पादन एवं पशु आहार प्रबंधन कार्यक्रम

ग्रामीण स्तर पर अच्छे किस्म के चारे का उत्पादन किसान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए चारा अनुसंधान द्वारा विभिन्न प्रकार के चारे की प्रजातियां निकाली गई है। उन्हें किसानो के खेतों तक पहुंचाकर उन्नत तरीके से उगा कर पशुओं को उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर एवं गौशाला स्तर पर दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। चारा उत्पादन हेतु प्रयास सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत चारा उत्पादन कार्यक्रम को भी बढ़ाया जाए। जिससे किसानों और डेयरी व्यवसायियों को तथा गौशाला की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अधिक बल मिलेगा।

(Table - III)

तालिका क्रमांक 03

चारा उत्पादन एवं पशु आहार की वर्तमान स्थिति

चारे का प्रकार	आवश्कता	उपलब्धता	चारा एवं आहार की कमी	
			कुल कमी	कमी का प्रतिशत
सूखा चारा	122.69	96.05	(-) 26.64	21.71
हरा चारा	368.09	58.42	(-) 309.67	84.13
पौषे	36.471	12.16	(-)24.31	66.66

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-3* June - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

Source – Brithal P.S. and Raju ss. (2006) microeconomic dimentianing Vhi & livestock souce by chhatiisgarh

1. फिर भी यह देखा जा सकता है कि राज्य में मुख्य रूप से चारा (सूखा चारा) में धान बड़े स्त्रोतों में उपलब्ध होता है और हरे चारे की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जंगलों और गोदामों से आता है।
2. पशुओं की नियमित स्थायी चराई के लिए राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 13% हिस्सा चारागाह के रूप में उपलब्ध है।

चलित पशु चिकित्सा परियोजना

वर्तमान में पशु चिकित्सालय ग्रामीण अंचल से दूर है जिससे पशुपालकों को पशु चिकित्सा में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि किसानों के पशु बीमार होते है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करने में देर हो जाती है एवं पशु की मृत्यु हो जाती है जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान बहुत होता है समय–समय पर सरकार द्वारा कई प्रकार की पशु चिकित्सा परियोजनाएं शुरू की गई परंतु किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शासन द्वारा चलाई जाने वाली पशु चिकित्सा सुविधाएं किसानों तक नही पहुंच पाती है इसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा की व्यवस्था में कमी। आंतरिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है एवं चिकित्सकों एवं अधिकारियों का अपेक्षापूर्ण व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार है । साथ ही पशु चिकित्सकों प्रति पशु संख्या लगभग (लगभग **8000** पशु पर एक चिकित्सक) वर्तमान में **32000** पशुओं पर एक चिकित्सक है जो कुल ¼ प्रतिशत की कमी होने को पशु कारण उनकी उपलब्धता नही होना भी मुख्य कारण है अतः पशुओं की उचित चिकित्सा तब हो सकती है जब तक पशुपालकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एवं पशु चिकित्सा से होने वाले लाभ से अवगत कराया जाए और पशु चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाए । यदि सरकार द्वारा चलित पशु चिकित्सा परियोजना को गांव गांव स्तर पर चालू किया जाए तो दुधारू पशुओं को मरने से बचाया जा सकता है एवं दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

(Table - IV) A=B

तालिका क्रमांक 04

(A)

वर्तमान में छ.ग. राज्य में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति

क्रमांक	वर्तमान में पशु चिकित्सों की उपलब्धता	भारत सरकार के मानदण्ड की अनुसार स्थिति	राज्य में पशु चिकित्सों की स्थिति	
			स्वीकृत पद	deh (Deficit)
1	क्षेत्रीय पशु चिकित्सक	2990	595	2395
2	Paravets	2095	1829	266

तालिका क्रमांक 04

(B)

पशु चिकित्सालयों की स्थिति

क्रमांक	राज्य में पशु चिकित्सक संस्थान	उपलब्ध	अपेक्षित	deh (Deficit)
1	पशु अस्पताल	208	593	पशु अस्पताल
2	पशु चिकित्सा औषधालय	738	1846	पशु चिकित्सा औषधालय
3	Poly Clinics	Nil	कुल 36–1 राज्य Polyclinics	
4	नैदानिक प्रयोगशाला	7	Only one DI Lab in State	

Source – C.G. livestock development agency (2008)

पशु पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह अनुभव किया गया है कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पशु पालन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव कम होता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार उचित ढंग से नहीं हो पाता है साथ ही जो प्रशिक्षण दिए जाते है उनकी पश्चातवर्ती देखरेख एवं अनुपालन नहीं किया जाता है जिससे प्रशिक्षण का सही लाभ नही मिल पाता है सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जो प्रशिक्षण किसानों एवं पशुपालकों को दिया जाता है उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इस कारण आधुनिक डेयरी फार्म प्रबंधन एवं डेयरी उत्पादन का विकास नहीं हो पा रहा है। अतः जब तक सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक इस प्रकार की परियोजनाओं का लाभ नही मिल सकता। यदि सरकार द्वारा या सहकारी संस्थाओं द्वारा आधुनिक डेयरी फार्म, प्रबंधन तथा आदर्श गौपालन एवं गौशाला प्रबंधन ग्रामीण स्तर पर किया जाए तभी डेयरी विकास हो सकता है दूध उत्पादन को बढ़ाना है तो किसानों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाए उन्हे डेयरी उत्पादन एवं प्रसंस्करण की नई तकनीकी से अवगत कराया जाए, ऐसे क्षेत्र जो दूध उत्पादन में कमजोर है वहां सही तरीके से लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए तो निश्चित ही दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

पशु प्रदर्शनी एवं पशु मेलों का आयोजन

पशुपालकों के प्रोत्साहन हेतु समय–समय आयोजन होने से उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इस

प्रकार के आयोजन से दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है, एवं डेयरी व्यवसाय के प्रति जागरूकता आती है इससे दूध व्यवसायी प्रभावित होकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने की चेष्टा करता है साथ ही आधुनिक तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। इस प्रकार के आयोजनों से दूध उत्पादन की नवीनतम जानकारी पशु पालकों को मिलती है, जैसे कि पशु का रखरखाव पशु चिकित्सा आहार प्रबंधन पशुओं का चयन, दोहन की विधियां कृत्रिम गर्भाधान पशुशाला का रखरखाव, नवीनतम प्रजनन विधियां, गुणवत्ता संबंधी जानकारी आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः पशु प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन कर कार्यक्रम एवं अन्य सहकारी सेवा संस्थानों द्वारा चलाया जाये, यह कहा जा सकता है कि दूध उत्पादन में वृद्धि सरलता से की जा सकती है।

कृषि एवं डेयरी व्यवसाय सहकारिता कार्यक्रम

कृषि एव डेयरी व्यवसाय सहकारिता कार्यक्रम यदि गैर सरकारी संस्थाएं द्वारा चलाया जाए तो दूध उत्पादन को बहुत संबल मिल सकता है। कृषि के साथ–साथ यदि डेयरी व्यवसाय कार्यक्रम को किसान अपनाता है तो निश्चित ही दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। वर्तमान में हुए कुछ अनुसंधान से यह पता चला है कि यदि किसान खेती के साथ डेयरी व्यवसाय करता है तो उसे इसका लाभ होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल इस योजना से संबंधित बनाए गए है जिससे यह पता चलता है कि किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यदि बनाये गये मॉडलों को सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाए तो निश्चित ही दूध के उत्पादन में दुगनी बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार के मॉडल सरलता से राष्ट्रीय संस्थाओं में उपलब्ध है जिसे प्रतिपादित करने में भी विशेष कठिनाई नहीं होती। इसे आसानी से ग्रामीण स्तर पर लागू कर दूध उत्पादन के साथ–साथ किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

(केरल मॉडल)

पशु पालकों एवं दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम

सरकारी एवं निजी संस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण किसान इस योजना की ओर ध्यान नहीं देते है। यदि सहकारी एवं सरकारी संस्था को जो लाभ होता है उसका कुछ भाग (लगभग 5% तक) दूध उत्पादकों एवं डेयरी व्यवसायियों को वितरित कर दिया जाए तो इससे उनको अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यदि इस प्रकार का कार्यक्रम व्यवस्थित चलाया जाए तो पशु पालकों एवं दुग्ध व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां बनाई जाए एवं समय–समय पर नियंत्रण रखा जाए तो दूध उत्पादन को संबल मिलेगा इस प्रकार के व्यवसाय कुछ राज्य में है, जैसे –गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब। यदि इसे सुचारु रूप से अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो अधिक दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

दुग्ध संकलन एवं उचित मूल्य निर्धारित कार्यक्रम

आज भी दूध संकलन की समस्या बनी हुई है। क्योंकि गांव में रहने वाले किसानों के द्वारा उत्पादित दूध के खरीददार नहीं है इसका मुख्य कारण सहकारी समितियों की कमी दूसरा दूध का उचित मूल्य न मिलना। यदि गांव स्तर पर छोटी–छोटी सहकारी समितियां बनाई जाए जो किसानों द्वारा उत्पादित दूध को उचित मूल्य पर क्रय कर सके। एवं इसके उत्पादन का सही मूल्य निर्धारण हो सके जिससे किसानों का दूध उत्पादन बढ़ाने में उत्साह वर्धन किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा तथा उचित मूल्य निर्धारण नीति बनाने की आवश्यकता होगी साथ ही प्रोत्साहन नीति बनानी होगी, तभी दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान तथा पशु पालक निराश हो जाते है एवं कुछ समय बाद इस व्यवसाय को बंद कर देते है। इससे यह आशय निकलता है कि किसानों को दूध एवं दुग्ध पदार्थों, उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके तब ही किसान प्रोत्साहित होकर डेयरी व्यवसाय को बढ़ा सकेगा।

सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन

"दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए" विषय पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि आज भी कई क्षेत्रों में कुछ सामाजिक कुरीतियां है, जैसे – बरवाही प्रथा और घरवाही प्रथा, अधिक मानदण्ड आदि जो कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आते है। बरवाही प्रथा में एक दिन का पूरा दूध ग्वाला को पशुपालक / किसानों द्वारा एक सप्ताह में दिया जाता है। जो कि एक सामाजिक बंधन है जबकि पशु पालकों का पूर्ण खर्च होता है । इसी कारण किसान उत्साहित न हो कर अपना व्यवसाय कभी–कभी बंद भी कर देता है। आज भी किसानों में घरवाही प्रथा है। जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है इसे बंद किया जाए तो दूध उत्पादन उन क्षेत्रों को दुगना किया जा सकता है। आज भी गांव में दूध बेचना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गाय को पूज्यनीय (गौमाता) माना जाता है। जो इसका दूध बेचता है उसे गांव के मुखिया द्वारा आर्थिक दंड या फिर उसका बहिष्कार किया जाता है। इसके लिए सामाजिक जन जागरण की आवश्यकता है जिससे इस प्रथा पर नियंत्रण किया जा सके।

उक्त कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी एव गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिए तभी कुरीतियों को समूल दूर किया जा सकता है तभी दूध उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है । दूध उत्पादन हेतु बताये गये इन दस बिंदुओं को अमल में लाने से दूध उत्पादन में 2 गुना बढ़ोतरी की जा सकती है तथा प्रत्येक नागरिक तक उचित मात्रा में दूध प्राप्त हो सकता है अभी तक जो 80 प्रतिशत दूध ग्रामीण अंचल से लाया जाता है यह एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है दूध संकलन व्यवस्था एवं गुणवत्ता नियंत्रण को प्रभावी रूप से सहकारी एवं गैर सहकारी संस्थाओं से मदद लेना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-3* June - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

उपरोक्त परियोजनाओं का उचित संचालन उचित डेयरी विकास की नई नीतियों को बनाने पर ही किया जा सकता है। एवं इससे सरकार की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन योजनाओं को संचालित करने हेतु आर्थिक सहायता की अधिक आवश्यकता होती है राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ किसान आयोग एवं गौसेवा आयोग का गठन कर तो दिया गया है परंतु डेयरी विकास के लिए ऐसा कोई विशेष आयोग या परिषद का प्रावधान नही किया गया है। यदि हमें इस नवगठित राज्य में जो आज किशोरावस्था में है, ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश अन्य प्रदेशों की भांति पिछड़ जाएगा। इसलिए आर्थिक विकास के वैकल्पिक कृषि डेयरी व्यवसाय पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि यह ऐसा व्यवसाय है जो अकाल, प्राकृतिक आपदा, भूखमरी, बेरोजगारी, अल्पवर्षा, अतिवृष्टि एवं निर्धनता को दूर करने में सक्षम है। इसलिए इस व्यवसाय को विशेष दर्जा देकर प्रदेश एवं गौशालाओं की आर्थिक उन्नति की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. पी. एल. चौधरी, (2006) छ.ग. राज्य में दुग्ध उत्पादन के नीतिगत पहलू, छ.ग.राज्य में व्यवसायिक चुनौतियां, वैशपेट प्रशिक्षण पुस्तिका*
2. *डॉ. पी. एल. चौधरी, (2016) छ.ग. में चारा उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में संभावनाएं , चारा उत्पादन एवं प्रबंधन*
3. *पी. एल. चौधरी, (2001) दुग्ध व्यवसाय के लिए नीति निर्धारण, छ.ग. खेती कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छ. ग.)*
4. *गौसम्पदा, (2019) पशु जनगणना वर्ष 2018 वर्तमान स्थिति का आकलन एवं परिदृश्य*
5. *P. L. CHOUDHARY (2006) Policy issues for chattisgharh dairy development, it's animal health and milk production book.*
6. *C.G. Livestock development agency (2008), action plan and recommendation for inhancement in livestocks.*

SSN 2394- 5303

Printing Area®

Issue-67, Vol-02 July-2020
Peer Reviewed International Refereed Research Journal

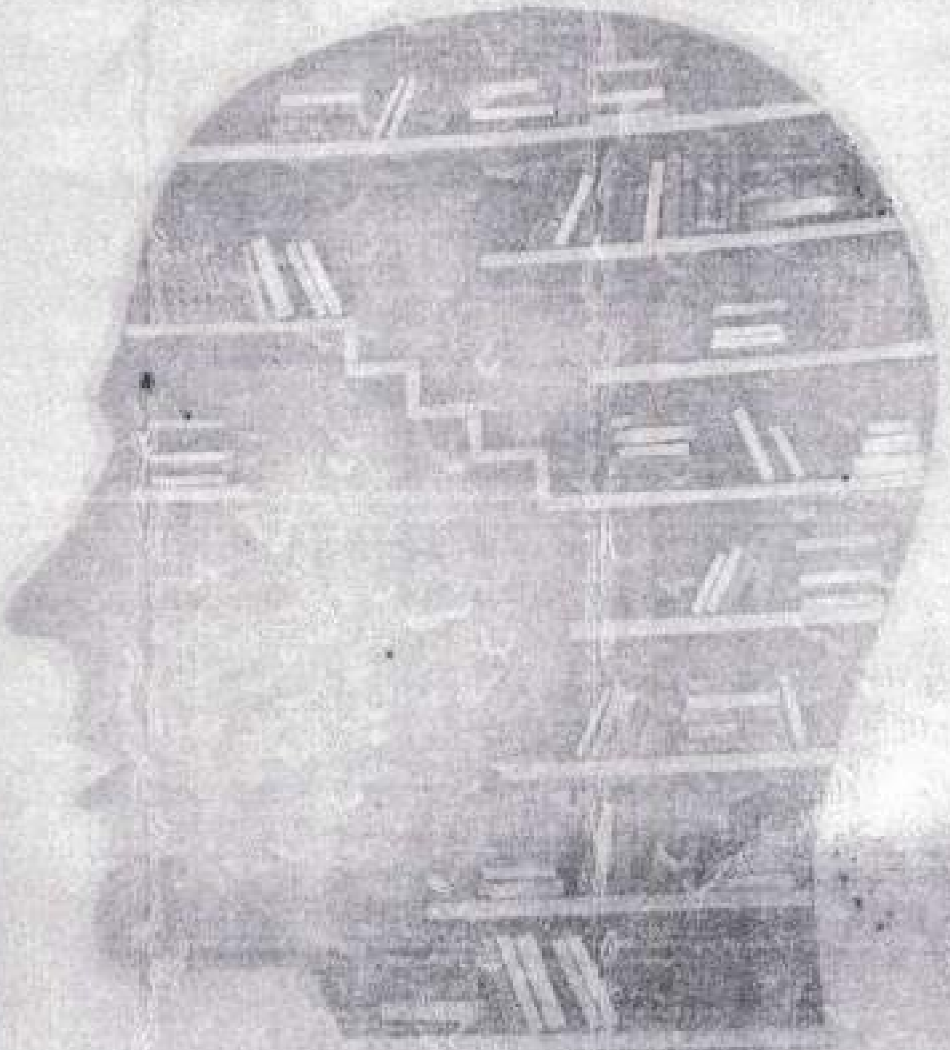

Editor
Dr Bapu G Ghol

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 7.387(IIJIF) | Printing Area® Peer-Reviewed International Journal | July 2020 Issue-67, Vol-02 | 0175

36

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित गौशाला प्रबंधन का विश्लेषण

(दुर्ग संभाग में संचालित विशेष गौशालाओं के संदर्भ में)

काव्या जैन
शोध छात्रा,
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. ए. एन. माखीजा
सहा.प्राध्यापक वाणिज्य,
शास.शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. पी. एल. चौधरी
निर्देशक,
कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.)

परिचय– भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां अधिकतर लोग कृषि का कार्य करके अपनी जीविका [illegible] करते है। गाय भारत जैसे कृषि प्रधान देश का [illegible] है। देश के अधिकतर भागों में कृषि के कार्यो [illegible] बैलों की मुख्य भूमिका होती है। जिससे देश में [illegible] प्राचीन काल से ही किसानों की आर्थिक स्थिति [illegible] सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। [illegible] में गौ स्तुति करते हुए लिखा है कि गाय [illegible] पूज्यनीय, पवित्र और संसार भर में उत्तम है। [illegible] देश की सभ्यता व संस्कृति से गाय जुड़ी है। [illegible] गोमय से ही बंजर जमीन को सुधारा जा [illegible] है, गोमय से ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती [illegible] हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि १८५७ का [illegible] संग्राम भी हमारे देश में गोमाता की हत्या को [illegible] ही आरंभ हुआ था। जब अंग्रेजों ने कारतूसों में गाय की चर्बी का प्रयोग किया तो सैनिकों को सहन नहीं हुआ। [illegible] मानव समाज के लिए सबसे [illegible]

भारत में हुए २०वीं पशुधन गणना [illegible] देश में कुल गोधन की संख्या १९२.४९ मिलियन (लाख) है जो पिछली गणना की तुलना में [illegible] प्रतिशत ज्यादा है। इसमें मादा गोधन १४५.१२ मिलियन (लाख) आंकी गई है। जो पिछली गणना २०१२ की तुलना में १८ प्रतिशत अधिक है।

हमारे पशुधन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारे देश में सब जगह की जलवायु, [illegible] की कमी में भी उत्पादन व बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। देश में इस समय गौ की ३० मान्य नस्ल है। इनकी संख्या कुल आबादी का केवल २० प्रतिशत है। शेष अवर्णित नस्ल की गाय है। उपयोगिता के आधार पर गौ नस्लें तीन प्रकार की है — दुधारू गौ नस्ले, दुकाजी गौ नस्ले और भारवाही गौ नस्लें लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इनका ठीक से सुधार, विकास नहीं किया है, दूध देने वाली नस्लों में साहीवाल, रेडसिंधी, थारपारकर, गीर, राठी व कांकरेज है। वर्तमान शोध बताते है कि इनकी क्षमता बहुत अधिक है इसलिए इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए इनके विकास की आवश्यकता है। कार्य के क्षेत्र में हमारी नस्लें बहुत अच्छी है लेकिन पिछले दो दशकों में कृषि के मशीनीकरण के कारण बैलों का महत्व कम हो गया है। छोटे किसानों द्वारा बैलों का पालना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहा वहां इनकी उपयोगिता कम हो गई।

भारवाही नस्लों की दुग्ध उत्पादन क्षमता आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। दूध बढ़ाने के लिए विदेशी नस्लों के संकरण की प्रक्रिया बिना नियोजन के [illegible] रही है। जिससे मान्य गौ नस्लो के पशुओं की संख्या कम हो रही है। इन संकर नस्लों के पूरे अध्ययन से पता चलता है कि ये ज्यादा समय तक [illegible] उत्पादन नहीं करती। इसके अलावा दूध का मूल्य [illegible] वसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है और गाय के दूध में वसा भैंस की तुलना में कम होता है। दूध के लिए किसान व व्यापारी वर्ग भैंसो को पसंद

Scanned By Scanner Go

करने लगे है। जिससे दूध देने वाली गाय की नस्ल मे भी कमी आयी है।

संकर नस्ल की गायो पर होने वाला खर्च अधिक है यह गाय हमारी बदलती जलवायु के अनुकूल भी नही है। इन सभी कारणों से फिर से किसान अपनी देशी नस्लों की गायो की मांग करने लगे है। वे किसान जिनके पास भूमि या तो है या बहुत कम है, उनका जीवन यापन मुख्यत: इन्ही देशी पशुओ से चलता है जो कि संख्या मे गिरावट झेल रहे है।

राष्ट्रीय आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल व अन्य संस्थाओ द्वारा भारतीय नस्लो की संख्या तथा उत्पादन जानने के लिए सर्वेक्षण किये गये इनमे पता चलता है कि दूध देने वाली नस्लें साहीवाल व रेड सिंधी की संख्या .बहुत कम हो गयी है। दुकाजी व भारवाही नस्लो की संख्या मे भी कमी आ गई है, ये सभी नस्लें खतरे मे है। व इनके सुधार व संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ भारत का २६वाँ राज्य है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का ७७% कृषि पर निर्भर है। ६४% कृषि पर नियोजित श्रम शक्ति है।

छत्तीसगढ़ राज्य मे २०१२ की जनगणना के अनुसार ९८.११ (लाख) पशुधन संख्या थी जो २०१९ में बढ़कर ९९.८४ लाख हो गई। अत: गौवंश की संख्या में १.७६: की वृद्धि हुई । जिसमे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे एवं अर्ध मध्य किसान परिवार लगभग ५०% गौवंशीय पशुओ एवं ५२% भैंस वंशीय पशुओं का पालन करते है । इससे स्पष्ट है कि ग्रामो के विकास हेतु पशुपालन की अहम भूमिका है।

२०१२ के आंकड़ो के अनुसार ११.८८ टन दुग्ध का उत्पादन छत्तीसगढ़ प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया जो २०१९ मे बढ़कर १२.८३ टन हो गया, अत: दुग्ध उत्पादन में ८% की वृद्धि हुई । दूध के व्यवसाय से सैकड़ो ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होता है, और इसके विक्रय से ही उनके परिवार का भरण पोषण होता है। गोवंश से प्राप्त दूध, दही, घी, गोबर एवं गोमूत्र पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही स्थान–स्थान पर महत्व बतलाया गया है। हमारा भारतवर्ष अभी कितनी ही अनगिनत समस्याओं से जूझ रहा है। इस वर्तमान अर्थव्यवस्था मे गोपालन एवं पंचगव्य ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हमारे गांव को पुन: आत्मनिर्भर बना सकती है। छत्तीसगढ़ मे विभिन्न प्रकार के पशुओं की प्रजातियां पाई जाती है, पर कोसली नस्लें छत्तीसगढ़ की नस्ले है। यहाँ गौपालन, गाय के गोबर से खाद, उपले बनाकर ईंधन के रूप मे भी प्रयुक्त किया जाता है। गौमूत्र से दवाईयाँ, फिनाईल तथा दही, घी, गौ दूध से उत्पादित किए जाते है। जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था मे प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस देश मे हर गांव, हर तहसील, हर जिले मे गौशालाओ की आवश्यकता है। आज गांव–गांव मे गौशाला को महत्व देते हुए गाय के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सजग होकर हम सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। गौशालाओं का उद्देश्य गौमाता को पालना ही नहीं अपितु गौमाता को भारत का अर्थव्यवस्था एवं समग्र विकास के रूप मे स्थापित करना है ।

भारत मे गोधन–पशुधन का बाहुल्य था जिसके फलस्वरूप भारत समृद्धिशाली एवं वैभवशाली था, परंतु आज की स्थिति बदल गई है। गाय जहां मनुष्य की समस्याओ का हल हुआ करती थी परंतु इस मशीन युग मे टेक्नोलॉजिकल विकास के दौर मे गाय की उपयोगिता एवं महत्व भी कम होती गयी। इस समस्या मे आवश्यक है कि गौमाता की उपयोगिता एवं महत्ता को जन मानस में पुन: स्थापित करें। इसमे गौशालाओं की अहम भूमिका है। लोगो को गौपालन के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना गौशाला का महत्वपूर्ण दायित्व है।

अध्ययन के उद्देश्य –

१. दुर्ग संभाग मे संचालित इन गौशालाओ मे पंचगव्य उत्पादो का परीक्षण करना।

२. दुर्ग संभाग की इन गौशालाओ मे पशु प्रबंधन की स्थिति व उन पर व्यय का विश्लेषण।

३. दुर्ग संभाग की इन गौशालाओ की आर्थिक व्यवस्था का पता लगाना ।

४. गौशाला संचालन से संबंधित समस्याओ

Scanned By Scanner Go

... का पता लगाना।

५. गौशालाओं के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त सुझाव देना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तावित शोध क्षेत्र दुर्ग संभाग में ५ जिले है, जिसमें कुल ६३ गौशालाएं संचालित है। अध्ययन हेतु संभाग की ३ गौशालाओं का चयन किया गया है। चयन का आधार वे गौशालाएं है जिनमें पंजीयन उपलब्ध होता है। चयनित गौशालाओं में एक राजनांदगांव, एक बालोद व एक बेमेतरा जिला क्षेत्र है। गौशालाओं के आर्थिक विश्लेषण व वर्तमान परिस्थिति की जानकारी हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक जानकारियां एवं आकड़े एकत्रित किए जाएंगे।

इसके साथ ही अध्ययन क्षेत्र में संचालित गौशालाओं के पशु प्रबंधन पर व्यय हेतु संबंधित जानकारियां एवं आकड़ो का संग्रहण गौशालाओं द्वारा प्रबन्धन में रखे गए लेख अथवा रजिस्टर्स से किया जायेगा। भारत छत्तीसगढ में गौवंशो की संख्या व उनसे प्राप्त उत्पाद संबंधी समंक वेबसाइट से प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकतानुसार द्वितीयक समंक गौशालाओं की वार्षिक प्रतिवेदन पत्रिकाओं व संबंधित वेबसाइट से एकत्रित किए जा सकते है। आकड़ों के विश्लेषण हेतु माध्य, प्रतिशत, आदि है।

भारत की गौशालायें – गाय का वास्तविक स्थान किसान का घर होता है। जब किसी कारण वश किसान को उसके पालन–पोषण में कठिनाई होती है तब वह गाय गौशाला आती है। इसलिए गौशाला को गाय के लिए आपातकालीन व्यवस्था के रूप में माना गया है। गाय की धार्मिक व सामाजिक महत्त्व की वजह से समाज के धार्मिक तथा सेवाभावी लोगों द्वारा देशभर में हजारों की संख्या में गौशालायें चलाई जाती है। हमारे देश में अनुमानित १५००० के आसपास विभिन्न नामों से गौशालाएँ कार्यरत है। जिसमें २० से २५ लाख लगभग गौ, भैंस, बछड़े का पालन होता है।

गौशाला स्वावलंबन – एक समय था जब गौशालाएं दान से प्राप्त हुए धन, चारे तथा अन्य वस्तुओं पर पूरी तरह से निर्भर होती थी। [illegible] दान से प्राप्त होने वाले [illegible] प्रकार के उत्पाद बनाकर [illegible] और जनकल्याण [illegible] गायों की संख्या [illegible] से स्वावलंबी गौशाला [illegible] के प्रबंधकों को [illegible] आवश्यक लगता है। इसका [illegible] उपयोग के लिए [illegible] गाय दूध के अलावा अन्य [illegible] पदार्थों को आवश्यक [illegible] गौशालाएं स्वावलंबी हो जाएगी। [illegible] स्वावलंबी होगी अपितु देश के [illegible] को भी काम मिल सकेगा।

गाय के दूध के अलावा [illegible] बहुत उपयोगी है। इससे तैयार [illegible] से जमीन की उर्वरा शक्ति [illegible] तुलना में इनका ९०% [illegible] अच्छी फसल प्राप्त होती है। [illegible] प्रति किलो के मूल्य से [illegible]

गौशालाएं गोमूत्र से [illegible] पेस्टीसाइड का अच्छा विकल्प [illegible] इससे देश में खरबों रुपए की [illegible] होगी। भारतीय गाय एक [illegible] गोमूत्र से कई प्रकार के रोगों [illegible] सकता है।

गौवंश आवास प्रबंधन – [illegible] हेतु उन्हें अधिक गर्मी सर्दी [illegible] आवश्यक होता है। इसलिए [illegible] की आवश्यकता होती है [illegible] हवादार बनाई जानी चाहिए। [illegible] बनी हो ताकि गायों को [illegible] हो। आवास १० फुट [illegible] बीच में चारे की गाड़ी आ [illegible] सकता हो। गौशाला [illegible] दूर होना चाहिए। गौशाला [illegible] पानी का नाला हो तो बहुत [illegible] न देने वाली तथा बछड़ो के लिए अलग अलग

Scanned By Scanner Go

आवास हो। गौशाला के बीच खुला आंगन हो जहां वह बैठ सके। एक गाय के लिए कम से कम ५ से १० फीट जगह काफी होती है। इसी अनुपात में भवन या बरामदे की जगह बनाई जा सकती है। बरामदे में एक ओर नांद बनी हो तथा फर्श पीछे की ओर ढलवां हो जिससे गोमूत्र बाहर निकल जाए। गौशाला में भूसा भरने, खली दाना रखने, चारा काटने की मशीन लगाने तथा गोरस रखने के लिए अलग–अलग भंडार होना चाहिए। चार पांच स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था हो तथा सप्ताह में एक बार उसे साफ करके चूने से पोतना चाहिए। प्रातः ६ से ८ बजे तक तथा सायं ५ से ६ बजे के बीच भी चारा डाले यदि दिन में कहीं चराने के लिए नहीं ले जा रहे है तो दोपहर में १२ से १ बजे के बीच भी चारा दिया जाए। गाय को चारे के साथ आधा किलो पका हुआ पशु आहार देना चाहिए। जल तथा विद्युत की ठीक व्यवस्था हो तथा गौशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे वातावरण में गोवंश पूर्ण रुप से स्वस्थ रहेगा।

छत्तीसगढ़ की गौशालाओं का सर्वेक्षण — छत्तीसगढ़ राज्य के २७ जिलों में कुल पशुधन की संख्या ९९८३९५४ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ९९ गौशालाएं संचालित है। जिनमें (बलरामपुर जिला — १, अंबिकापुर — ४, सूरजपुर — २, रायगढ़ —७, बिलासपुर —७, कोरबा —६, जांजगीर चांपा — १०, मुंगेली— २, रायपुर— ५, बलौदा बाजार— ५, महासमुंद—३, गरियाबंद—१२ धमतरी — ५, दुर्ग — ३, राजनांदगांव —७, बेमेतरा—६, कबीरधाम— ३, बालोद —४, कांकेर—२, कोंडागांव—४, जगदलपुर—१.) गौ सेवा आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न जिलो में ९९ पंजीकृत गौशाला है। जिसके माध्यम से गौ संवर्धन हेतु कार्य किया जाता है। इन गौशालाओं में साहीवाल, गीर, थरपारकर, कौशली, हरियाणा सिंधी, कांकरेज आदि नस्ल पाई जाती है। इनमें कुछ गौशालाओं का उद्देश्य जीव दया है। कुछ गौशालाएं गोवंश के गौ मूत्र व गोबर से दवाइयां भी बना रही है। कुछ गौशालाएं में गोबर गैस प्लांट, गोबर की लकड़ी बनाने की मशीन लगाई गई हैं। तो कुछ गौशालाओं में जैविक कृषि अपनाई गई है। कुछ गौशालाएं बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन का कार्य कर रही है। तो कुछ गौशालाएं गोवंश के पूर्ण विकास पर कार्य कर रही है। इन गौशालाओं में शुद्ध नस्ल की गाय देखने में कम ही आई है। कुछ अच्छी और अग्रसर गौशालाओं में अच्छी नस्ल की गाय होने के बावजूद उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अलग प्रजनन का प्रबंध भी नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण शहर दुर्ग जहां पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत अंजोरा में फ्रोजन बुल स्टेशन की स्थापना की गई है। दुर्ग शहर दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जिला है। दुर्ग संभाग में २३ गौशालाएं संचालित है, जिनमें लगभग ५००० गोवंश की संख्या है।

तालिका क्रमांक . ०१

छ.ग.राज्य में गौशालाओं में गोवंश एवं उस पर व्यय

क्र	गौशाला की ...	वर्ष	गोवंश की संख्या	पशु आहार: व्यय (लाख रु.)	पशु आहार: वृद्धि/कमी (%)	बिजली: व्यय (लाख रु.)	बिजली: वृद्धि/कमी (%)	[illegible]
१	श्री गौशाला पिंजरापोल राजनांदगांव	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	[illegible]	[illegible]	— 2.95% कमी 18.3% वृद्धि 9.12% कमी	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२	[illegible]	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	[illegible]	28.70 [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३	[illegible]	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	[illegible]	[illegible] [illegible] 9.46 19.56	— 44.57% [illegible] 25.12% [illegible] 106.76% [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] 0.25	[illegible]	[illegible]

स्त्रोत — संग्रहित द्वितीयक समंकों पर आधारित

विश्लेषण — तालिका क्रमांक १ से ज्ञात है कि छ. ग. राज्य के विभिन्न जिलो में स्थापित गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि–

१. श्री गौशाला पिंजरापोल राजनांदगांव में वर्ष २०१५–१६ में पशुओं के आहार व्यय पर २.९५% की कमी थी जो २०१६–१७ में पशुओं की संख्या बढ़ने पर १८.३१% की वृद्धि हो गयी किन्तु २०१७–१८ में पशुओं की बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप पशु आहार में ९.१२% की कमी पायी गयी। इस प्रकार तीनो वर्षो का माध्य निकालने पर पशु आहार में कुल २.०७% की वृद्धि आयी।

Scanned By Scanner Go

SSN: 2394 5303 | Impact Factor 7.387(IIJIF) | Printing Area® Peer-Reviewed International Journal | July 2020 Issue-67, Vol-02 | 0179

२. तालिका क्रमांक ०१ के आधार पर श्री [illegible]वीर गौशाला एवं अनुसंधान केन्द्र बालोद व श्री [illegible]म गौशाला जीव रक्षा व अनुसंधान केन्द्र आन्दु के [illegible]नो वर्षो के पशु आहार में कुल ०.८% व ४२.०३% [illegible] वृद्धि हुई ।

[illegible]लिका क्रमांक — ०२

[illegible]शालाओं में आदानों की स्थिति

[illegible] २०१८.१९

	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]त — संग्रहित द्वितीयक समंको पर आधारित ।

[illegible]शाला प्रबंधन की समस्याएं —

लोगों में गौशालाओं के प्रति विश्वास आस्था [illegible]आदर तो है । लेकिन आज की परिस्थितियां बदल [illegible]है। कुछ लोग गौशालाओं को आर्थिक लाभ के [illegible]श्य से कार्य संचालित कर रहे है साथ ही कुछ [illegible]गो ने गौशालाओं की भूमि जो चरने के लिए उपयोग [illegible] आती थी उसी पर ही कब्जा कर लिया है। [illegible]तीसगढ़ मे गौशाला की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है [illegible]सकी वजह से गौशाला को गाय बछड़े के रखरखाव [illegible] सदैव परेशानी बनी रहती है। गौशालाओं के प्रबंधन [illegible] बहुत सी समस्याएं आती है —

- गौशालाओं मे सेवादारों तथा पैसो की कमी ।
- गौशालाओं में चारा दाना खरीदने के लिए [illegible] की कमी है जिसके कारण गोवंश को सही मात्रा [illegible] चारा प्राप्त ना होने के कारण बीमारियां व कमजोरी [illegible] वजह से उनकी मृत्यु हो रही है।
- गौशालाओं में प्रबंधन की कमी ।
- गौशालाओं में अच्छे सांडों की कमी, तकनीकी [illegible] की कमी, गौशाला मे आपसी तालमेल का ना [illegible], चारे — दाने पर खर्चे में वृद्धि ।
- पशु चिकित्सक की सलाह पर ध्यान नहीं [illegible]है। तथा गौशाला में बीमार पशुओं का सही समय [illegible] इलाज नही हो पाता।
- अज्ञानता की वजह से गौ आधारित औषधी निर्माण का अभाव ।
- [illegible] गौशालाएं पंचगव्य [illegible] नहीं रही है, गौमूत्र, गोबर का सही [illegible] से भी गौशालाओं का विकास नही [illegible] है।

छत्तीसगढ़ गौशालाओं कि आर्थिक [illegible] चिंताजनक है। कुछ ही गौशालाओं [illegible] खाद निर्माण एवं पंचगव्य आधारित [illegible] निर्माण किया जाता है अनेक गौशाला सिर्फ [illegible] पालन पर ही ध्यान देती है। प्रशिक्षण के अभाव [illegible] उचित मार्गदर्शन के अभाव मे गौ—उत्पादित [illegible] के निर्माण न किये जाने से पालन—पोषण [illegible] में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गौशालाओं की समस्याएं अनेक है इनके सुधार की आवश्यकता है।

गौशाला को उन्नत बनाने हेतु सुझाव

- स्वदेशी प्रजाति के पशुओं का अधिक संरक्षण एवं विकास करना। अच्छे बैल, सांड [illegible] करने पर ध्यान केंद्रित करना ।
- पशु आहार एवं चारा आदि की समुचित व्यवस्था हेतु उन्नत किस्म के बीजो के उपयोग पर बल दिया जाना ।
- गोवंश ऊर्जा का अखंड स्रोत है गोबर गैस संयंत्र लगाने पर बल। बैलों का अधिकतम सदुपयोग, बैल चलित कृषि यंत्रो, जनरेटर व पम्प सेट आदि के सदुपयोग पर बल।
- खेती का कार्य बैलों से करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे [illegible] कार्य करने वाली नस्लो के सुधार पर जोर दिया जा सके।
- गाय के गोबर और गोमूत्र का प्रयोग [illegible] रासायनिक खादों की अपेक्षा जैविक कृषि को [illegible] दिया जाए, ताकि बंजर होती हुई जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके।
- गौशालाओं में जो देशी दवाईयां उपयोग में आती है उन पर पूरी जानकारी प्रदान करना चाहिए ।
- प्रत्येक जिला स्तर पर एक गौशाला को आदर्श गोशाला बनाया जाए ताकि अन्य गौशालाओं को भी मार्गदर्शन मिल सके ।

Scanned By Scanner Go

• प्रत्येक राज्य स्तर पर गोष्ठियां व मेले आयोजित कराई जाए जहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके, व उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

• गौशाला में प्रबंधकों द्वारा गौशाला को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । जिसमें पंचगव्य उत्पादन के महत्व को समझा जाए ।

• किसानों, गोशाला प्रबंधकों, बेरोजगारों के लिए जैविक कृषि, जैविक खाद एवं कीटनाशक गोपालन, गोविज्ञान गौशाला प्रबंधन आदि उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था।

निष्कर्ष –

शासन स्तर पर गाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए पंचगव्य के महत्व एवं उसकी उपयोगिता को गौशाला प्रबंधकों के बीच रखकर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान में गौमाता का संरक्षण, संवर्धन हेतु गौशाला के पास पर्याप्त स्रोत नही है। आर्थिक तंगी की वजह से गौशाला संचालित करने गौशाला प्रबंधन मंडल को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान अर्थव्यवस्था में गौपालन एवं पंचगव्य ही एक मात्र ऐसी शक्ति है जो हमारे गांव को पुनः आत्मनिर्भर बना सकती है। अतः आवश्यकता है समय–समय पर पंचगव्य की उपयोगिता रेखांकित करते हुए प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करके स्वावलंबी गौशाला स्वावलंबी ग्राम हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

• मित्तल डॉ सतीश चंद्र, (२००९), गो–अमृत, राष्ट्रीय गौ सम्पदा विकास एवं प्रबंधन संस्थान एवं राष्ट्रीय गोवंश विकास प्रकोष्ठ भाजपा, नई दिल्ली ।

• पुंडीर राकेश कुमार, (२००७) The Indian Cow, The scientific and economic journal, Miss asha swami, Love 4 cow Trust New Delhi.

• डॉ रणवीर सिंह, (२००९), गो–अमृत, राष्ट्रीय गौ सम्पदा विकास एवं प्रबंधन संस्थान एवं राष्ट्रीय गोवंश विकास प्रकोष्ठ भाजपा, नई दिल्ली

• http://agriportal.cg.nic.in/ahd/ahdHi/default.aspx

• http://m-jagranjosh-com.cdn.amproject.org/v/s/m.jagranjosh.com

Scanned By Scanner Go

ISSN : 2456-4397 Bilingual / Monthly RNI : UPBIL/2016/68067 Vol-5/ Issue-10/ January-202

Anthology The Research

Impact Factor
SJIF(2020)=6.018
IIJIF(2018)=4.02

Indexed-with Google scholar

Peer Reviewed / Refereed Journal

पेक्ष में साहित्य (एक अवलोकन) ना, देहरादून, उत्तराखण्ड, भारत	H-80 to H-82
े आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका गुप्ता, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	H-83 to H-85
कश्मीररू वस्तुस्थिति और बदलाव जारीबाग, झारखण्ड, भारत	H-86 to H-91
नकों का सांस्कृतिक इतिहास वीर रस के संदर्भ में एवं रामावतार मीना, टोंक राज. भारत	H-92 to H-96
शैली का वर्तमान स्वरूप मनगर, उत्तराखण्ड, भारत	H-97 to H-99
राजनीतिक चिन्तन और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	H-100 to H-103
क्षण की पर्याय हड़प्पा सभ्यता : उत्थान एवं पतन भरतपुर, राजस्थान, भारत	H-104 to H-107
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दलितों की भूमिका ोनवानी एवं फुलसो राजेश पटेल, राजनांदगांव, छ.ग. भारत	H-108 to H-110
बालाघाट जिले में आधुनिक षिक्षा का विकास ऐतिहासिक विवेचन (1867 से 1975 श्याम, छिंदवाड़ा, भारत	H-111 to H-114
य के विकास में हरियाणा की भूमिका ैल, कैथल हरियाणा, भारत	H-115 to H-117

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021
Anthology : The Research

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दलितों की भूमिका
Role of Dalits in the First Freedom Struggle of 1857

Paper Submission: 15/01/2020, Date of Acceptance: 26/01/2020, Date of Publication: 27/01/2021

आई. आर सोनवानी
प्राचार्य,
इतिहास विभाग,
शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव,
छ.ग. भारत

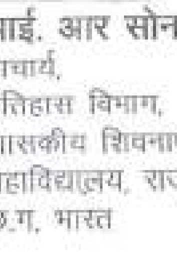

फुलसो राजेश पटेल
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव,
छ.ग. भारत

सारांश

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध है। कई इतिहासकारों ने इसे महान विद्रोह, किसानों का विद्रोह, सिपाहियों के द्वारा असंतुष्ट होकर किया गया सिपाही आन्दोलन तथा राजा–महाराजा या प्रादेशिक राजाओं के द्वारा किया गया विद्रोह माना है। भारतीय इतिहासकारों ने सर्वमान्य से इस बात को स्वीकार किया है कि, पहली बार भारत के समस्त वर्ग जिसमें राजा–महाराजा, साधारण किसान, हिन्दू–मुस्लिम तथा भारत में रहने वाले जनसामान्य वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर इस आन्दोलन में भाग लिया था। यद्यपि तथाकथित कारणों से यह महासंग्राम सफल नहीं हो सका तथापि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसे जन आन्दोलन के नाम से परिभाषित किया है। इस आन्दोलन में भारत में रहने वाले दलित वर्गों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

The freedom struggle of 1857, India's first freedom struggle is famous as a very important freedom struggle from historical, political, economic and cultural point of view. It has been considered by many historians to be a great revolt, peasant revolt, the Sepoy movement made by the soldiers disgruntled and the revolt by the king-maharaja or territorial kings. Indian historians have universally accepted that, for the first time, all sections of India, including the King-Maharaja, ordinary peasants, Hindu-Muslims and the masses of people living in India, also stood shoulder to shoulder for the first time to overthrow the British power. Took part in this movement together. Although this Mahasangram could not succeed due to so-called reasons, however, it has been defined by Indian historians as the people's movement. The Dalit classes living in India have also contributed significantly in this movement, their contribution cannot be forgotten.

मुख्य शब्द : स्वतंत्रता संग्राम, हिन्दू–मुस्लिम, साधारण किसान, इतिहासकारों।
Freedom Struggle, Hindu-Muslim, Ordinary Farmers, Historians.

प्रस्तावना

1857 का महासंग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से अभिभूत है क्योंकि इसमें भारतीय समाज के प्रत्येक तबके के लोग समर्पित होकर भाग लिये थे। आलोच्यकाल में 1857 के क्रांति में दलितों की भूमिका को रेखांकित कर प्रकाश में लाना लाजमी प्रतीत होता है इससे दलितों को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने में मार्ग प्रशस्त होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता आन्दोलन में दलितों के द्वारा सक्रिय रूप से स्वाधीनता आन्दोलन में भूमिका का निर्वहन किया है। जिसे इतिहास के अकोशलताओं को जानना जरूरी है। इस आन्दोलन में भारत के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा जाति–पाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग आदि के भेदभाव को भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर दलितों ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था। इनके योगदान को इतिहास के पृष्ठों पर अंकित करना या राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से केन्द्रित होकर यह शोध पत्र उल्लेखित है।

विद्रोह बंगाल आर्मी तक सीमित नहीं था। भूस्वामी, कुलीनों के अलावा जनसामान्य ने भी इस महान विद्रोह में मदद की थी और देश के विभिन्न हिस्सों में इस महान राष्ट्रीय घटना से जुड़ी कार्यवाहियों में शिरकत की थी। इस तथ्य से सभी सहमत है कि 1857 की महान क्रांति की शुरूआत चर्बी वाले कारतूस की घटना से शुरू हुई थी प्रोफेसर अरूण बंधोपाध्याय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री आफ गन एण्ड शैल फैक्ट्री, कासीपुर में लिखा है कि वैसे तो सैन्य औजारों का उत्पादन देश के विभिन्न हिस्सों में, कम्पनी के प्रयोग शालाओं में होता था लेकिन बंगाल में एक आयुध फैक्ट्री के निर्माण की पहली सुव्यवस्थित कोशिश उन्नीसवीं सदी के मध्य में शुरू हुई। चूंकि दमदम लम्बे अर्से से बंगाल आर्टिलरी का केन्द्र बना हुआ था अतएव उसे ही कारतूसों की टोपियों के उत्पादन तथा उसकी मरम्मत स्थल के रूप में चुना गया था और 1846 में ब्रिटिश भारतीय सेना की भयंकर हार से निकला था। इस फैक्ट्री को इसी प्रयोजन से स्थापित की गई थी। यह महत्वपूर्ण निर्णय बहुत हद तक 1841–42 के अफगान अभियान में ब्रिट्रिश भारतीय सेना की भयंकर हार का प्रतिफल था। इस फैक्ट्री में छोटे हथियारों के लिए कारतूस बनाने वाला एक हिस्सा भी था और गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को लेकर समस्या यहीं से शुरू हुई थी । (1) एच.आई.एस.कंवर ने अपनी पुस्तक "मैमोअर्स आफ दमदम" में चिकनाई लगे कारतूसों के मसले पर रोशनी डाली है। वे लिखते हैं कि अट्ठारह सौ सत्तावन की जनवरी के मध्य में दमदम में गोली बारूद फैक्ट्री के निकट एक ऐसी घटना हुई जिसके बहुत ही दूरगामी नतीजे निकले। इस संबंध में कंवर लिखते हैं कि एक नीची जाति के लश्कर या मैग्जीन में काम करने वाले की जब कैन्टूनमन्टे में एक ऊँची जाति के सिपाही से भेंट हुई, उसने अपने लोटे से पानी पीने के लिए कहा। ब्राम्हण सिपाही ने जाति की याद दिलाते हुए नाराजगी से उसे जवाब दिया। इस पर उस लश्कर ने व्यंग्य से उससे कहा कि जल्द ही ऊँची जाति और नीची जाति सब एक ही जाने वाले हैं क्योंकि सिपाहियों के लिए ही डिपुओं में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस बनाये जा रहे हैं और जल्द ही पूरी सेना में उनका इस्तेमाल आम फहम हो जायेगा। (2) कंवर आगे लिखते हैं कि वास्तव में वह दूषण सिपाहियों के होंठों तक आ जाने वाला था। यह कोई कल्पना नहीं थी कुछ समय पश्चात् दिखाई देने वाला यह तथ्य सच्चाई था।

इसलिए इसका असर हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों के मन में घृणा की तीव्र भावनाएं उभरकर सामने आने के रूप में हुआ। (3) ऐसा समझा जाता है कि जिस ब्राम्हण सिपाही को निचली जाति के लश्कर ने ताना मारा था वह और कोई नहीं मंगल पांडे था। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली होने की बात को सुनकर मंगल पांडे उबल पड़ा था 29 मार्च को दमदम फैक्ट्री के … मैदान पर उसने अचानक मारे जाने से एडजुटेंट तथा सार्जेंट मेजर को बचा लिया। बाद में मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया । (4) शेख पल्टू को मेजर हैरसे ने पदोन्नत कर जमादार बना दिया, कटाक्ष करने वाले लश्कर की पहचान मातादीन भंगी के रूप में की गयी है।

इलाहाबाद के जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ सोसल साइंस के बद्रीनारायण तिवारी ने यह रेखांकित किया है कि 1857 का विद्रोह इस अर्थ में अनोखा था कि इसमें समाज के विभिन्न तबके के लोग एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे लेकिन इस क्रम में किसी खास ग्रुप के वृहत्तर समग्रता में विलीन नहीं होना पड़ा था, जबकि गांधी वादी युग में ऐसा हुआ था। (5) मातादीन भंगी के भूमिका की चर्चा करते हुए वह लिखते हैं "एक बहुत ही संकीर्ण परिप्रेक्ष्य देखकर ही यह जाना जा सकता है कि निचली जातियों का 1857 के विद्रोह से कुछ लेना देना नहीं था। परन्तु इन दबे कुचले लोगों के हथियारों एक पंहुच न होने के चलते सशस्त्र संघर्ष में भले ही हिस्सा न लिया हो, फिर भी उन्होंने आन्दोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा भरी थी जिसके बिना यह संघर्ष वह रूपाकार ले ही नहीं सकता था, जो उसने ग्रहण किया"। (6) मातादीन भंगी के कटाक्ष के संबंध में तिवारी लिखते हैं– बहरहाल अचरज की बात है कि ज्यादातर लोग एक निचली जाति के व्यक्ति के शरारती कटाक्ष का महत्व समझ पाने में विफल ही रहे है परन्तु नीची जाति के मातादीन भंगी के शब्दों ने वास्तव में स्वाभिमान जगाने का काम किया था और सवर्ण मंगल पांडे तथा उनके जैसे लोगों के सदियों से सोये पड़े आत्म गौरव को जगाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। इसी तरह "बलीराम महेतर तथा चेतराम जाटव के नाम राष्ट्रीय पुनरोदय की शानदार मिसालों के तौर पर सामने आते है। निचली जाति में जन्में इन दोनों लोगों को, जो बैरकपुर के विद्रोहों से शुरू हुए बगावतों के सिलसिले में कूदपड़े थे।

ब्रिट्रिश अफसरों के आदेश पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक पेड़ में बांधकर उन्हें गोली मार दी गयी थी"। (7) उस युग में निचली जाति के अनेक नायक – नायिका के नाम सामने आये हैं जिसमें मातादीन के अलावा बलीराम महेतर, चेतराम जाटव, झलकारी बाई, उदा देवी, वीरापासी, बंशके चमार तथा दूसरे अनेक लोग शामिल है। (8)

इतिहासकार एम.एस. जगप्रकाश मंगल पांडे को 1857 के सिपाही विद्रोह का पहला योद्धा मानने से इंकार करते है। इनका कहना है कि इस प्रकरण में पहला अभियुक्त मातादीन भंगी को बनाया गया था, जिसे ब्रिटिश अदालत ने सजा दी थी और फांसी पर चढ़ा दिया था। (9) मंगलपांडे को इस प्रकरण में दूसरा अभियुक्त बनाया गया था। सन 1997 में पटना में 28–29 सितंबर को अवर्ण साहित्य सम्मेलन में इस विषय पर अनेक लेख – सामने आये इनमें से एक लेख ने रेखांकित किया गया था कि सिपाहियों के जरिए स्वतंत्रता के युद्ध का बीज बोने … था। उसमें कारतूसों में पशु

उत्तर प्रदेश (मैनपुर) से प्रकाशित अखबार– अनार्य भारत 15 अगस्त 1996 के अंक में लिखा है कि इसके बाद सभी हिन्दू सिपाहियों ने विद्रोह की योजना बनाई। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा तैयार की गई चार्ज शीट में अन्य अभियुक्तों के साथ मातादीन का नाम अभियुक्त संख्या एक के रूप में आया है। मातादीन को सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया गया था (11) दलित साहित्यकार जी.सी. दिनकर, आचार्य भगवान दास भी इस तथ्य को स्वीकारते है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महागाथा में दलितों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दलितों के योगदान को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। सन् 1857 ई. का युग यह दिखाता है कि, समाज अर्न्तविरोधों से उबरते हुए एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होने में समर्थ था । वास्तव में आज के दौर में उस जमाने से सीख ले सकते हैं और सभी सामाजिक तबकों को इसका शिक्षा देकर कि उनके पुरखों ने एकजुट होकर साझा शत्रु के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे प्रेरणा लेकर सुदृढ़ राष्ट्र एवं समाज की विकासशील आयाम गढ़ी जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *गुप्ता मुरारी लाल –हिस्ट्री आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पृ – 260*
2. *श्रीवास्तव रामसेवक (अनुवादक) 1857 स्वतंत्रता संग्राम पृ – 33*
3. *लोक लहर– 9 दिसंबर – 2007 में प्रकाशित लेख*
4. *पूर्ववत*
5. *मार्क्स और एंगेल्स भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857– पृ – 11*
6. *सी.पी.आई. प्रकाशन प्रभाकर विजय (अनुवाद) 1857 का संग्राम पृ – 13*
7. *लोक लहर 9 सितंबर 2007 में प्रकाशित लेख*
8. *पूर्ववत्*
9. *पूर्ववत्*
10. *तिवारी बी.एन. इकानामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 31 अगस्त 2004 प्रकाशित लेख*
11. *जयप्रकाश एम.एस. द हिन्दू 26 अगस्त 2005 प्रकाशित आलेख*
12. *अवर्ण साहित्य सम्मेलन– 28–29 दिसम्बर 1997 रिपोर्ट*
13. *अनार्य भारत– 15 अगस्त 1996 बी.एन. तिवारी का प्रकाशित लेख,तथा दिनकर डी.सी. स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान – पृ – 37*

ISSN : 2456-5474
RNI : UPBIL/2016/68367
Bi-lingual/Monthly
Vol-3-Issue-9-October-2018

Social Research Foundation

Innovation
The Research Concept

Peer Reviewed Multi-disciplinary
Bi-lingual International Journal

Impact Factor
SJIF = 3.420
IIJIF = 4.112

S R F

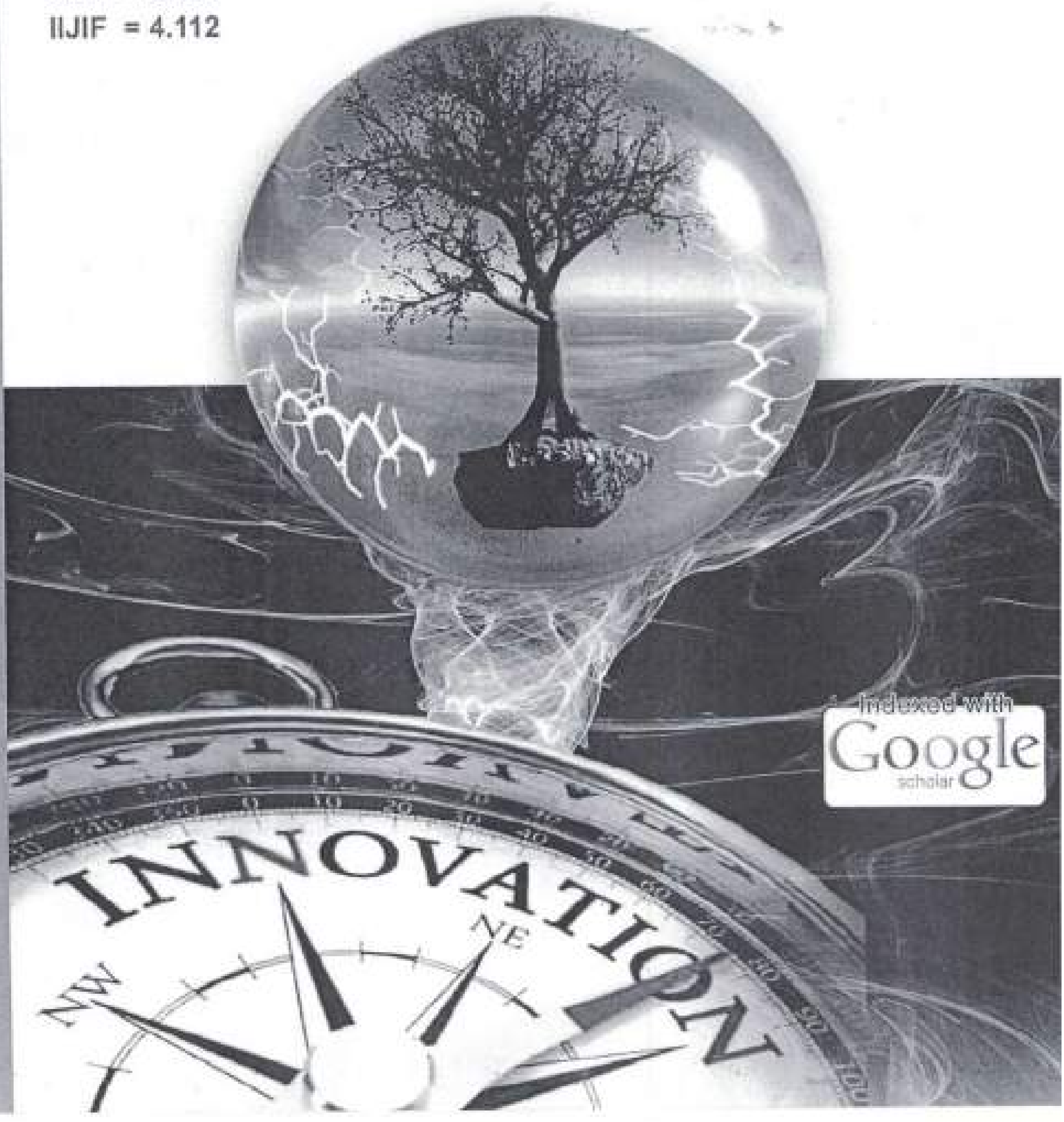

Indexed with Google scholar

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-9* October- 2018
Innovation The Research Concept

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1.	नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र में नौकरशाह की भूमिका आबेदा बेगम, राजनांदगांव (छ.ग.)	01-02
2.	छत्तीसगढ़ में प्रचलित गउरा गीत बी. नन्दा जागृत, राजनांदगांव (छ.ग.)	03-06
3.	घरेलू हिंसा एक पारिवारिक विघटन एलिजाबेथ भगत, राजनांदगांव (छ.ग.)	07-09
4.	आजादी के सात दशको में भारत की विकास यात्रा एक अध्ययन नागरत्ना गनवीर, राजनांदगांव (छ.ग.)	10-13
5.	बुद्ध का धम्म मानवता, मैत्री एवं विश्व शांति का मार्ग नीलिमा बागड़े, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	14-16
6.	राजनीतिक अपराधीकरण प्रियंक कुमार रोकड़े, दन्तेवाड़ा, छ.ग.	17-18
7.	पर्यावरण बचाने की चिंता एस. आर. कन्नोजे, राजनांदगांव (छ.ग.)	19-20
8.	महिला सशक्तिकरण– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिखा सरकार, दन्तेवाडा, छ0ग0	21-23
9.	पर्यावरण अवनयन : विकास से विनाश की ओर सरिता स्वामी, बलोद, छत्तीसगढ़	24-27
10.	कृषक आन्दोलन फुलसो राजेश पटेल, राजनांदगांव, छ.ग.	28-31

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-9* October- 2018
Innovation The Research Concept

कृषक आन्दोलन

फुलसो राजेश पटेल
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय,
राजनांदगांव, छ.ग.

सारांश

सदियों से अब तक, दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में, कन्दराओं और गुफाओं की खुली हवा में स्वछन्द मानसिकता अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले, परिवार, समाज, राष्ट्र के जन–जन तक दो वक्त की रोटी जुटाने की कशमकश में, कठोर परिश्रम अधिक फसल उगाने की जुनून, निःस्वार्थ भाव से खून पसीना बहाकर, अनाज पैदा करने के लिए अपने आपको खेत खलिहान में समर्पित करता है– ''कृषक''। आँधियों और तूफानों के भंवर में, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, तपती दोपहरी चिलचिलाती धूप के गर्म शोलों के भट्ठी में झुलसते हुए, कड़कड़ाती ठंड की ठिठुरन सर्द हवाओं में अर्द्धनग्न वस्त्र धारण कर सबकी भूख मिटाने के लिए अनवरत कार्य करता रहता है – ''कृषक''।

मुख्य शब्द : कृषक आन्दोलन।

प्रस्तावना

सहस्त्र वर्ष पहले से कृषकों पर कृषि कर के रूप में शोषण और अत्याचार होता आ रहा है।[1] प्राचीनकाल में [2] राजा–महाराजाओं ने भूमि कर के रूप में कृषकों पर कर लगाया। नवाबों, सुल्तानों तथा सम्राटों, शासकों तथा पेशवाओं ने मध्ययुग में लगान के नाम पर कृषकों का शोषण किया है।[3] सामंती युग में, सामंतों के द्वारा कृषकों से बेगार में खेती कराकर संपूर्ण कर का बोझ ही उन पर थोप दिया। कृषक कर के बोझ से कराह उठा।[4] आधुनिक युग में ब्रिटिश जंजीरों में जकड़ा राष्ट्र औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के शिकंजों में जकड़े कृषकों को जमींदारी प्रथा, रैय्यत वाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था[5] ने कृषकों को किंर्तव्यविमूढ़ बना दिया। आदि से अब तक देश काल परिस्थितियों के थपेड़ो में कर के बोझ को सहन करने की धैर्य, सहन शक्ति, कृषकों में विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ। आदिकाल से अब तक शोषित, दमन, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कृषकों के द्वारा किया गया –''कृषक आंदोलन है।'' देश के सभी भागों में अलग–अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति को परिवर्तन करने के लिए आवाज बुलंद किया, उसे ही कृषक आंदोलन के रूप में जाना जाता है।

विषय प्रवेश

प्राचीनकाल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। यहां के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि है। लगभग 80 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सिन्धु सभ्यता के समय से ही कृषक देश एवं समाज के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करता आया है। वैदिक काल में कृषि कार्य को मुख्यतः आय का स्त्रोत माना जाता था।[6] महाकाव्य काल में भू–राजस्व लगान की मनमानी नहीं की जा सकती थी। शासकों द्वारा महाकवि कालिदास ने अपने चर्चित ग्रंथ में लिखा है जिस प्रकार सूर्य हजार गुना बढ़ा कर देने के लिए पृथ्वी से जल खींचता है, उसी प्रकार राजा दिलीप प्रजा कल्याण के लिए ही उनसे कर (लगान) लेता है।

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत।
सहस्त्र गुणमुत्स्रष्टुमादत्तेहि रसं रविः।।[7]

महाभारत में भी राजाओं को चेतावनी देते हुए लिखा है – जो राजा प्रजा की आय का छठवां भाग कर के रूप में वसूल करता है किन्तु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे सम्पूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया

है।[8] मौर्यकाल में कृषकों के हितों के लिए अनेक सुविधाएं दी जाती थी किन्तु कृषकों को राज्य के लिए कर देने पड़ते थे। गुप्तकाल में गुप्त शासकों के द्वारा कृषि उत्पादन हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं सुविधाएँ दी जाती थी। प्राचीन काल में किसान आंदोलन का उल्लेख नहीं मिलता है।[9] मध्यकाल में कृषकों की समस्याएँ अधिक थी। मध्यकाल में सामंतवादी व्यवथा के कारण कृषकों से कर लिया जाने लगा। जिससे कृषकों की स्थिति खराब होती गयी। पूर्व मध्यकाल में फिरोज तुगलक के शासनकाल में अनेक सुधार योजनाएँ चलाये गए। मध्यकाल में शेरशाह सूरी प्रथम शासक था, जिसने कृषकों की स्थिति को समझा तथा कृषि के क्षेत्र में कृषकों के मांग के आधार पर सुधार किया। अकबर के समय सामंतवादी व्यवस्था का आरम्भ हो चुका था। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के काल में अकाल पड़ा था, स्वाभाविक तौर पर कृषक समस्या पर अध्येयताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ।[10]

आधुनिक युग में औपनिवेशिक शासन ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर ढाया। साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियाँ भू–राजस्व की नई प्रणाली एवं उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू किया उनसे बेगार ली जाने लगी। उनसे मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूल करने का एक दुश्चक्र चल पड़ा। परिणामस्वरूप किसान धीरे–धीरे महाजनों के चगुंल में फंसते गया और इस तरह उनकी जमीनें, फसले और पशु उनके हाथ से निकल कर जमींदारों, व्यापारियों महाजनों और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते गए। छोटे किसानों की हैसियत महज काश्तकारों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति में रह गई। किसानों ने इस दमन को चुपचाप सहन नहीं किया उन्होंने कई स्थान पर जहाँ–जहाँ, जब–जब उन पर शोषण हुआ, तब–तब छुटपुट विद्रोह किये।[11] उनकी एक भीषण प्रतिक्रिया 1857 के महान विद्रोह के समय में देखने में आई जब लाखों किसानों ने देशी राज्यों का साथ दिया।[12]

20वीं सदी के शुभारंभ 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उपरांत राष्ट्रीय समस्यों पर चर्चा कर ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जाता था किन्तु किसानों के समस्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने अकाल के प्रकोप और ऋण के आंकड़े में डूबे किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत 1919 में किसानों ने विद्रोह आरम्भ कर दिया।[13]

कृषक आंदोलन के उद्देश्य – कृषक आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित है

1. कृषकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाए।
2. जमींदारी प्रथा का अंत किया जाए।
3. फसल पैदावार से जमीन के आधार पर कर लिया जाए।
4. बेगार प्रथा को बंद किया जाए।
5. गैर कानूनी ढंग से छीनी जमीन कृषकों को वापस किया जाए।
6. माल गुजार, साहूकार, पूंजीपतियों से कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा किया जाए।
7. कृषकों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक।
8. खेतिहर कृषकों को उचित मजदूरी प्राप्त हो।[14]

प्रमुख कृषक आन्दोलन

कृषकों पर हो रहे अत्याचार, शोषण एवं दमन की नीति तथा औपनिवेशक साम्राज्य के विरूद्ध उक्त उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु भारत के अलग–अलग क्षेत्र पर कृषकों द्वारा आंदोलन किया गया। कृषक आंदोलन निम्नलिखित है[15] :–

1. संथाल विद्रोह (बिहार) 1855–56 ई.
2. बंगाल में नील 1859–62 उत्पादकों की हड़ताल
3. मालाबार में मोपला संघर्ष 1873–80 ई.
4. मराठा कृषक विद्रोह– 1875 ई.
5. आसाम में 1893–94 कृषक आंदोलन
6. चम्पारन सत्याग्रह 1917–18 ई. (बिहार)
7. खेड़ा किसान आंदोलन (गुजरात) 1918
8. दरभंगा का किसान आंदोलन (बिहार) 1919–20
9. पंजाब का कृषक आंदोलन 1920–21
10. उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन 1920–21
11. एका आंदोलन 1921–22 ई.
12. बरदोली सत्याग्रह 1929–30
13. बिहार में अमवारी किसान सत्याग्रह 1939
14. पुनप्पा वायलर संघर्ष त्रावणकोर (केरल) 1929–30
15. तेलंगाना कृषक आंदोलन 1946–51 ई.

संथाल विद्रोह

1810 से 1870 तक बंगाल के आसपास व संथाल के गांवों में हजारों किसानों ने संथाल विद्रोह किया। विद्रोह का दमन कर दिया गया।[16]

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों की स्थिति

1857 ई. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों ने भी भाग लिया तथा अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया, किन्तु इसके असफल होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सरकार 1859 ई. में अधिनियम पारित किया। 1859 ई. रेट अधिनियम एक्ट लागू किया गया। किसानों से वसूल की जाने वाली लगान को बढ़ा दिया गया।[17]

नील विद्रोह

1879 ई. में मराठा कृषकों ने विद्रोह कर दिया कृषकों ने साहूकारों के घरों व दुकानों पर आक्रमण किए तथा उन्हें जला डाला। सरकार ने इस तरह विद्रोह को

कठोरता पूर्वक दमन किया तथा इस विद्रोह के कारणों को पता लगाने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग की स्थापना की। 1879 ई. में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिससे कृषकों को कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई।

पंजाब में कृषकों का असंतोष

अपनी खराब स्थिति को सुधार करने के लिए पंजाब के किसानों में विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी। 1900 ई. में सरकार ने पंजाब भूमि असंक्राम्य अधिनियम पारित किया। जिसमें किसानों को कुछ सुविधाएँ दी गई।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा कृषक आंदोलन

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की गति बढ़ती जा रही थी भारतीय कांग्रेस ने भारत के कृषकों की खराब स्थिति का तो उल्लेख किया। किन्तु उसको सुधारने के लिए विशेष कांग्रेस के द्वारा कृषकों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया।

चम्पारन विद्रोह

1917 ई. में महात्मा गाँधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। बिहार के चम्पारन जिले में नील की खेती करने वाले किसानों को उनके यूरोपीय मालिकों द्वारा प्रताड़ित किया गया। गाँधी जी ने कृषकों की स्थिति का अध्ययन किया तथा किसानों को संगठित कर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। अन्ततः सरकार को तिनकठिया पद्धति किसानों की भूमि उससे छीन ली गई थी उसे समाप्त कर दिया गया।

बरदोली आंदोलन

बम्बई सरकार ने लगान में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इसके विरुद्ध कृषकों ने बरदोली में विद्रोह किया। 1922 ई. में चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन पुनः प्रारंभ किया तथा किसानों को संगठित किया जिससे किसानों में संगठन, एकता शक्ति के समक्ष सरकार को उनकी मांगे मानने के लिए विवश होना पड़ा।

असहयोग आंदोलन व कृषक

महात्मा गाँधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1921 ई. में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था तथा इस आंदोलन से कृषकों के साहस में वृद्धि हुई तथा कृषक संगठित होकर विरोध करने लगे।

मोपला विद्रोह

1921 ई. में मालाबार क्षेत्र मोपला विद्रोह हुआ। प्रारंभ में यह अंग्रेज सरकार के विरुद्ध था। 1925 ई. में कामगार तथा किसान दल बना। 1927 ई. में किसान बिहार "किसान सभा" तथा 1936 ई. में "अखिल भारतीय किसान सभा" की स्थापना हुई। इससे राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठित हुए।

तिभागा आंदोलन

बंगाल में किसानों ने 1936 ई. में तिभागीय बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध फसल की तीन–चौथाई भाग किसानों को दिये जाने के लिए चलाया गया था। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के कृषक इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। सरकार एवं जमींदारों के विरुद्ध संपूर्ण बंगाल के कृषकों ने आंदोलन किया। यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ–साथ स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा।

तेलंगाना आंदोलन

हैदराबाद के किसानों ने 1946 ई. में निजाम व रजाकारों के विरुद्ध 1946 ई. में आंदोलन चलाया। आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त हुआ। कालांतर में 1949 में जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त किया गया।

इस प्रकार हम देखते है कि जमींदारों और जागीरदारों के द्वारा कृषक शोषण, भू–राजस्व कर में वृद्धि, भूमि से बेदखली, ऋणों का बोझ, बेगार एवं अन्य प्रकार कर से कृषक उत्पीड़ित थे। यह आंदोलन किसी एक क्षेत्र के जनता का आंदोलन नहीं था अपितु संपूर्ण भारत के भिन्न–भिन्न क्षेत्र में आंदोलन होता रहा। किसान आंदोलन कृषकों पर अत्याचार के विरुद्ध अवश्य ही था किन्तु राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ही आधारित था। कृषक जनता में जनप्रचार, तथा जागृति लाने का काम मुख्यतः सभाओं, सम्मेलनों, रैलियों प्रदर्शनों एवं किसान सभाओं के गठन द्वारा किया गया। कृषक आंदोलन ने परम्परागत जमींदारी व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी शासन की जड़े खोद दी।[18]

निष्कर्ष

हमारे देश के लाखों मेहनतकश किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं फिर भी उनका कल्याण लम्बे अरसे से दर किनार है।[19] कृषक की समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न क्षेत्र में अलग–अलग समय में आंदोलन हुआ तथापि यह आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन का आधार बना रहा। आजादी के उपरांत भी कृषकों का उचित समाधान नहीं हो पाया है। समय–समय पर स्वतंत्र भारत में अलग–अलग समय में कृषि नीति में परिवर्तन होता आया है। वर्तमान में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार कृषि उत्पादन में लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही जिसके कारण उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण कृषकों के द्वारा आत्महत्याएँ की घटनाएँ घटित हो रही है।[20] 2018 के विधान सभा के परिणाम में कृषक असंतोष प्रमुख कारण रहा है तथा सत्ता परिवर्तन राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा गया है।[21] 2019 लोकसभा चुनाव का मुद्दा आदिवासी एवं कृषक है।[22] भारत सरकार ने तत्कालीन

कृषकों की समस्या के लिए समुचित नीति तैयार कर कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। कृषक के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से हमें भोजन, वस्त्र और फल–फुल प्राप्त हो रहे हैं। उनके हितों की रक्षा का उत्तर दायित्व शासन के साथ–साथ समस्त देश के नागरिकों का भी कर्तव्य है। हमें हर संभव उनके हितों की सुरक्षा करना होगा।

"जय हिन्द"

"जय जवान – जय किसान"

संदर्भ–ग्रंथ–सूची

1. भारत का सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, डॉ.एस.आर. शर्मा, पृ. 35–309
2. दिल्ली सल्तनत का इतिहास, डॉ. आर्शीवाद लाल श्रीवास्तव, पृ. 334, 335 व 336
3. मुगलकालीन इतिहास, डॉ. आर्शीवाद लाल श्रीवास्तव, पृ. 404, 405 व 406
4. मध्यकालीन यूरोप का इतिहास, पृ. 101, आधुनिक पाश्चात्य इतिहास की मुख्य धाराएँ, पृ. 289
5. इतिहास, बी.के श्रीवास्तव पृ. 173.
6. इतिहास चिंतन, प्रो. रमेन्द्रनाथ मिश्र, डॉ. सचिन मंदिलवार पृ. 202
7. कालिदास रघुवंश प्रथम सर्ग–18.
8. महाभारत भाग–I पृ. 609
9. इतिहास, बी. के श्रीवास्तव, पृ. 181
10. आधुनिक भारत, पी.एल. गौतम, पृ. 665, 66 व 67
11. प्रो. रमेन्द्रनाथ मिश्र, डॉ. सचिन मंदिलवार पृ. 202.
12. आधुनिक भारत पी.एल. गौतम पृ. 605,
13. भारत के किसान संघर्ष, मैकमिलन कम्पनी 1980, पृ. 11 से 18.
14. इतिहास बी.के श्रीवास्तव पृ. 181
15. वही पृ. 176
16. वही
17. आधुनिक भारत, पी.एल. गौतम पृ. 181 से 184
18. योजना, जुलाई 2018 पृ. 45
19. दैनिक भास्कर 15 नवंबर 2018
20. दैनिक भास्कर 22 नवंबर 2018
21. नईदुनिया 12/03/2019.
22. दैनिक भास्कर 15/03/2019

ISSN : 2456-4397 (P)
Bilingual / Monthly
RNI : UPBIL/2016/68067
Vol.3 - Issue - 9 - December - 2018

Multi-disciplinary Bi-lingual International Journal

Anthology
The Research

Impact Factor
SJIF = 3.39
IIJIF = 4.02

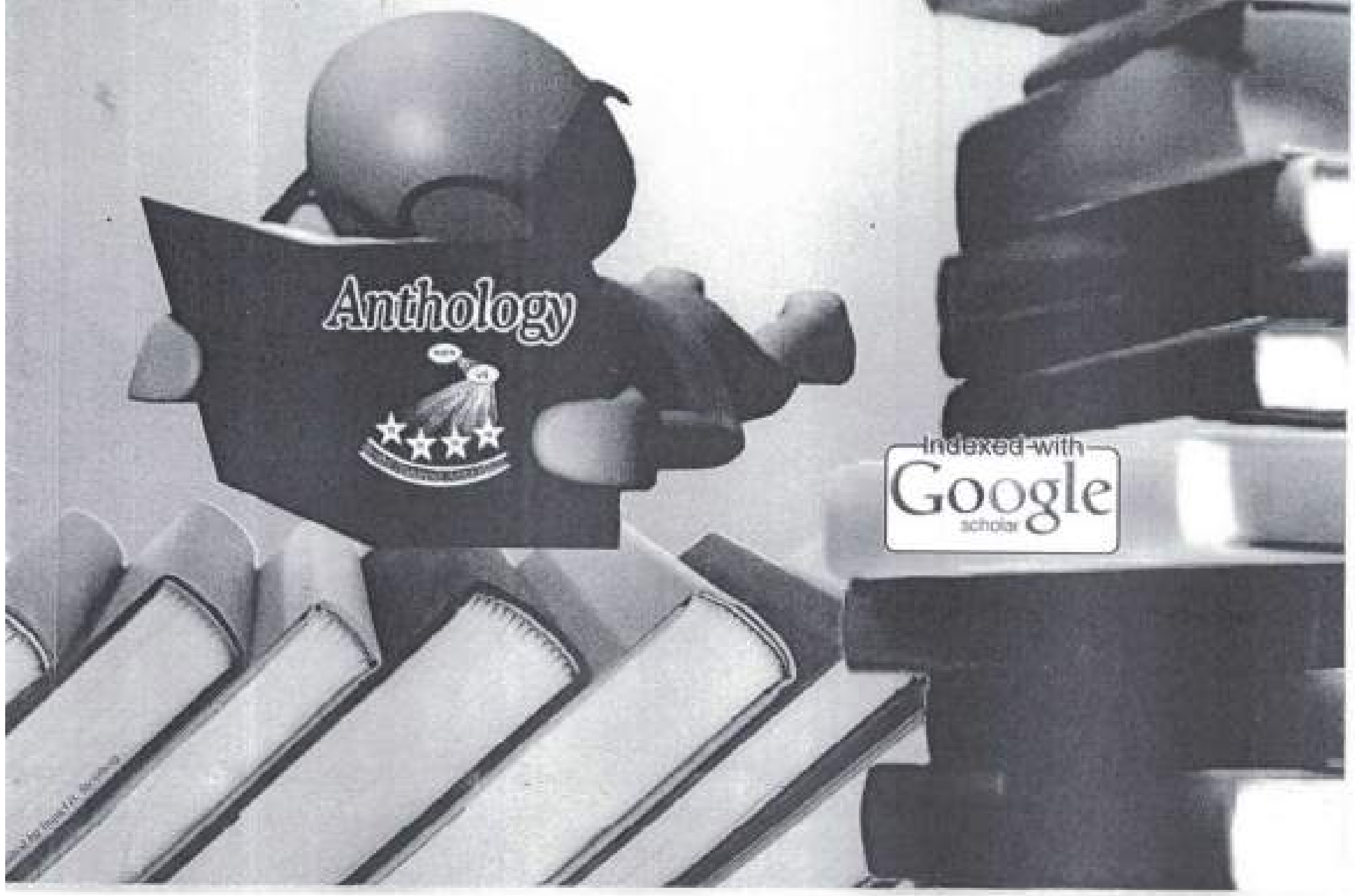

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-3* Issue-9* December- 2018
Anthology : The Research

Contents

S. No.	Particulars	Page No.
1.	बाल सुरक्षा– पारिवारिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों की भूमिका एलिजाबेथ भगत, राजनांदगांव, छ.ग.	01-04
2.	साहित्य एवं पत्रकारिता बी. नंदा जागृत, राजनांदगांव, छ.ग.	05-08
3.	राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान फुलसो राजेश पटेल, राजनांदगांव (छ.ग.)	09-11
4.	चुनाव में मीडिया की भूमिका (2014 के लोकसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में) नागरत्ना गनवीर, राजनांदगांव	12-14
5.	भारत में खाद्यान्न सुरक्षा–एक विवेचन शुभा शर्मा, दुर्ग, छ.ग.	15-18
6.	राजनीति प्रकिया में महिलाओं की दशा एवं दिशा सुशमा चौरे, राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़	19-22
7.	छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ (जिला बालोद के विशेष संदर्भ में) अनुग्रहती जॉन, बालोद, (छ.ग.)	23-26
8.	महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका आबेदा बेगम, राजनांदगांव (छ.ग.)	27-29
9.	दलित महिलाओं का सशक्तिकरण : एक अध्ययन मालती तिवारी, महासमुन्द, छ.ग.	30-33
10.	पंचायतीराज संस्थाएँ एवं महिला सहभागिता सरिता स्वामी, बलोद, छत्तीसगढ़	34-36

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-3* Issue-9* December- 2018
Anthology : The Research

राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान

फुलसो राजेश पटेल
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
शास. शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

सारांश

इतिहास गवाह है कि – आदिकाल से ही राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा है। बड़े–बड़े राष्ट्रों के उत्थान–पतन तथा युद्ध का मुख्य कारण नारी रही है। राष्ट्र के नव निर्माण, उत्थान में योग्य पुत्रों को जन्म देकर लालन–पालन कर अपने रक्त का अमृतपान कराकर राष्ट्र को सींचा है। कभी रणचण्डी बन कर राष्ट्र की रक्षा में अपने शत्रुओं का नरसंहार किया है तो कभी सशक्त एवं शक्तिशाली शासिका बन कर शासन सत्ता संचालन किया है। कभी विष कन्या बनकर दुश्मनों को विषपान कराया है तो कभी नृत्यांगना बन कर सबके सुख–चैन को छीना है।

मुख्य शब्द : राष्ट्र का विकास, उत्थान–पतन, महिलाओं का योगदान।

प्रस्तावना

प्राचीनकाल के धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में उल्लेख है– "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते है।[1] शक्ति, विद्या, धन, स्वरूपा नारी की पूजा सदियों से होती चली आ रही है। तत्कालीन जीवन एवं जगत के हर क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, ज्ञान–विज्ञान हो अतीत के पन्नों में भारत के ज्ञान का कोई क्षेत्र न था जहां उसकी प्रतिभा मंडित न हुई हो।[2] अनेक वेद मंत्रों के अवतरण ऋचाओं के दृष्टा के रूप विश्ववारा, गोधा, अपाला, घोषा, शची, लोपामुद्रा आदि ऋषिकाओं का सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। गार्गी अरूंधती की गिनती सर्वोच्च सप्तऋषिओं मे की जाती है।[3] अनुसुईया सप्तऋषिओं का नेतृत्व करती थी। पुराणों में देवताओं तथा राक्षसों के मध्य युद्ध में देवीशक्ति रणचण्डी का रूप धारण कर दैत्यों का नरसंहार करती है। सरस्वती, दुर्गा तथा लक्ष्मी पूजा उनकी अद्भुत शक्ति को दर्शाते है।

जब पृथ्वी पर भगवत अवतरण की आवश्कता हुई तब मनु के साथ उनकी पत्नी सतरूपा के तपस्या के फलस्वरूप सतरूपा ने कौशिल्या बन कर, रामजी को गोद में खिलाया था। कृष्ण जन्म भी माता अदिति की तपस्या का परिणाम था। राजा भरत जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था, जंगल में माता शकुन्तला ने ही पालन–पोषण किया था।[4]

महर्षि पुलोमा की पुत्री शची से इन्द्र ने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर विवाह किया था। मनु के बाजपेय यज्ञ को उनकी पुत्री इला ने यज्ञाचार्य के रूप में अनुष्ठान को सम्पन्न कराया। महाराज जनक के दरबार में महाविदुषी गार्गी एवं महर्षि यज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ इतिहास प्रसिद्ध है। यज्ञवल्क्य को गार्गी के पाडित्य एवं वैदुष्य का लोहा मानना पड़ा। इस युग मे विदधा, उद्धलिका, वीचावली, अनुसुईया, यमी, सूर्या इस काल की प्रख्यात विदुषियॉं थी।[5] तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक शनैः शनैः नारी की शक्ति और स्वरूप में अन्तर दृष्टिगोचर होने लगा। रामायणकाल में सती साध्वी अहिल्या को इन्द्र द्वारा छल–बल से पति एवं समाज में तिरस्कृत होना पड़ा। माता सीता को अपने सतीत्व का अग्नि परीक्षा ही नहीं अपितु मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम से परित्याग का दारूण दुःख झेलना पड़ा, महाभारत काल में द्रौपदी को चीरहरण का अपमान सहना पड़ा।[6]

मध्ययुग में महिलाओं पर सामाजिक कुप्रथाएं एवं कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, पर्दाप्रथा इत्यादि प्रचलित

थी, इस युग में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, इसके बावजूद इस युग में रजिया सुल्तान को भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। चाँद बीबी, रानी दुर्गावती, नूरजहाँ, जीजा बाई, ताराबाई तथा मुमताज महल ने मध्यकालीन अंधकार युग में अपनी यशस्वी अमिट छाप छोड़ी है।[7]

भक्तिकाल में मीरा बाई, मुक्ता बाई, केशगा बाई, गंगुबाई भक्ति की प्रमाणिकता मानी जाती है।[8] आधुनिक युग में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए सभी प्रकार की पारिवारिक–सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों को तोड़ते हुए देवी चौधरानी, साहब कौर, रानी शिरोमणि, भीमाबाई, लुनाचिदार, चेनम्मा, साम्राज्य लक्ष्मी देवी वीरतापूर्वक अंग्रेजों को टक्कर दी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्रांति का नेतृत्व कर स्वतंत्र भारत के लिए बलिदान हो गई। बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, रानी तेजबाई सुल्तान, जमानी बेगम, महारानी तपस्विनी, कुमारी मैना, नर्तकी अजीजन, मंजू शहदेवी, मेहरी, माही, कृषक महिला न जाने कितनी असंख्य महिलाओं ने क्रांति में अपने आपको होम कर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी।[9]

19वीं सदी के आरम्भ में भारतीय समाज में स्त्रियों के शोषण के विरूद्ध महिलाओं की दशा में सुधार के लिए अनेक समाज सुधारकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनमें प्रमुख थे– राजाराम मोहनराय, ईश्वर चन्द विद्यासागर, वीर सालिंगम, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविन्द रानाडे, बालगंगाधर तिलक, महात्मा ज्योतिबाफूले, मालाबारी गोपालकृष्ण आगरकर, हरि देशमुख इत्यादि। महिला सुधारकों में पण्डित रमाबाई, रामाबाई रानाडे, स्वर्ण कुमारी देवी, स्वर्णमयी, सावित्री बाई फूले, आनन्दी बाई जोशी ने अपना योगदान दिया।[10] विभिन्न आंदोलनों के अध्ययन से स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, पर्दाप्रथा, बाल–विवाह, सती प्रथा, नेहिर प्रथा का अंत किया गया, जिससे स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़–चढ़कर पुरूषों से कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दिया। मां शारदा देवी, भगिनी निवेदिता, फ्रांसिना सोराबाजी, लेडी हरनाम सिंह, माता सावित्री बाई फूले, शांता तिलक, सत्यभामा तिलक, बाया कर्वे, लेडी सदाशिव अइय्यर, डॉ. इडास्कर पूनम लुकोज, मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी, श्रीमती चन्द्रशेखर अइय्यर, श्रीमती गुरूशेखर, सरला नायक, रंगम्मा धनवंती रामाराव, माधवी अइय्यर, शारदा मेहता, ऐनी बीसेंट, सरोजनी नायडू, बेगम मां भोपाल, चारूलता मुखर्जी, सरला देवी चौधरी, सरला रे, लेडी अबला बोस, हीरा बाई टाटा, जानकी बाई भट्ट, अवंतिका बाई गोखले, शांता तिलक, ऐसू बाई सावरकर समाज सुधार तथा राजनीतिक क्षेत्र में अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान की।[11]

आजादी की लड़ाई में समाज सुधारकों के आह्वान पर नारी जागृति एवं प्रगति का शंखनाद किया गया। परिणामतः समाज सुधार व देश की आजादी के संयुक्त लक्ष्य में स्त्री–पुरूष भेद–भाव भुलाकर कदम से कदम मिलाकर स्वाधीनता महायज्ञ की आहूति में कूद पड़े। कालांतर में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन में लाखों स्त्रियों ने सभी प्रकार के भेद–भाव को भुलाकर घरों से निकलकर भागीदारी ही नहीं बल्कि आंदोलन को सफल बनाने में नेतृत्व प्रदान किया। भीका जी कामा जी, ऐनीबीसेंट, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरूणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कैप्टन लक्ष्मी अग्रणी महिलाएँ जिनके नेतृत्व एवं निर्देशन में असंख्य उत्साही युवतियां आगे आई और इनसे प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दी। इससे महिलाओं में नई चेतना का विकास हुआ तथा यही चेतना बाद में स्त्रियों की प्रगति का आधार बनी।[12]

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं को महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। श्रीमती सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती लक्ष्मी पंडित रूस, इंग्लैंड, अमेरिका की राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य, अरूणा आसफअली दिल्ली महिला मेयर के दायित्वों को निर्वहन करने का उत्तरदायित्व दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वाधिक समय तक प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।[13] महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विदेश मंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री, सभापति अध्यक्ष, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्राथमिक अधिकारी, सहायिका, गृहणी, ग्राम पंचायत मुखिया, मजदूर, खेतखलिहान एवं अन्य क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। आज के परिप्रेक्ष्य में महिला शक्ति पुरूषों के सैन्य शक्ति पर एकाधिकार के वर्चस्व को भी तोड़ा है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2019 के परेड में महिलाओं द्वारा लड़ाकू विमान का अद्भुत प्रदर्शन साक्ष्य रहा है।[14]

आज की नारी आकाश में उड़कर चाँद–तारों के पास पहुँच रही है। फिर भी दहेज की बलि चढ़ा दी जा रही है। संविधान में समान अधिकार प्राप्त है। अवसर के सभी दरवाजे खुले है। क्यों और कैसे ? ये प्रश्न महिलाओं के साथ घर, परिवार, समाज तथा राष्ट्र का है। महिलाओं को सशक्त शक्तिशाली बनना है। इसके लिए महिलाओं को स्वयं को आगे आना होगा और अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा।

राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में महिलाओं की भूमिका आज दुनिया के सामने प्रतिबिंबित है –

आज हमारे देश की महिलाएँ पूरी
दुनिया के सामने चुनौती बन रही है
और सबसे अपना लोहा मनवा रही
है।
धरती से अंतरिक्ष तक और देश से
दुनिया तक
हर कहीं वह अपने अस्तित्व के
साथ मौजूद है।
घर गृहस्थी के बाहर आज महिलाएँ
सचमुच शक्ति का प्रतीक बनकर
उभरी हैं।

वह चाहे उद्योग हो या प्रक्षेपास्त्र के अतिरिक्त पुलिस, सेना, वकालत, राजनीति, शिक्षा है या थियेटर, पेंटिंग, अभिनय, साहित्य, पत्रकारिता, डिजाइनर, गायिका, नृत्यांगना, एथलिट हो या फिर जबरदस्त आंदोलनकारी।[15] सभी क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ रही है एवं राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मनुस्मृति 3/56, राष्ट्र गौरव, वेद विभाग, शांति कुंज, हरिद्वार, युग चेतना ट्रस्ट, उत्तराखंड पृ. 64
2. ऋग्वेद, 10/85, 21वीं सदी–नारी, पं. श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय पृ. 2.39
3. तैत्तरीय ब्राम्हण, राष्ट्र गौरव पृ. 66
4. राष्ट्र गौरव, वेद विभाग, शांति कुंज, हरिद्वार, युग चेतना ट्रस्ट, उत्तराखंड पृ. 66
5. वैदिक साहित्य 5/14, प्रभासभा, महिला विकास और सशक्तिकरण पृ. 2
6. चंद्रवती लखनपाल, स्त्रियों की स्थिति पृ.25, मनुस्मृति 5/148
7. महिलाएँ और स्वराज्य, आशा रानी व्होरा, प्रकाशन विभाग भारत सरकार 1999, पृ. 8 व 9
8. महिलाएँ और स्वराज्य, आशा रानी व्होरा, प्रकाशन विभाग भारत सरकार 1999, पृ. 9
9. मोजम्मिलहसन आरजू, भारतीय महिलाएँ एवं आधुनिकीकरण, पृ. 11, 12, 13
10. महिलाएँ और स्वराज्य, पृ. 91
11. आधुनिक भारत, पृ. 91
12. महिलाएँ और स्वराज्य, पृ. 92 से 101
13. राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 20वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध शासकीय विलासा पीजी कॉलेज बिलासपुर, इतिहास विभाग, पृ. 57
14. गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर प्रातः 10:00 बजे दूरदर्शन से सीधा प्रसारण, उद्धृत।
15. एक से एक शिखर महिलाएँ, संगीता अग्रवाल, हिन्दी पॉकेट बुक्स, पृ. 1

ISSN (P) : 2456-5474 RNI : UPBIL/2016/68367 Bi-lingual/Monthly Vol.-6* Issue-5* June- 2021

Innovation

The Research Concept

Multi-disciplinary Bi-lingual International Journal

Peer Reviewed / Refereed

Impact Factor
SJIF = 6.122
IIJIF = 4.112

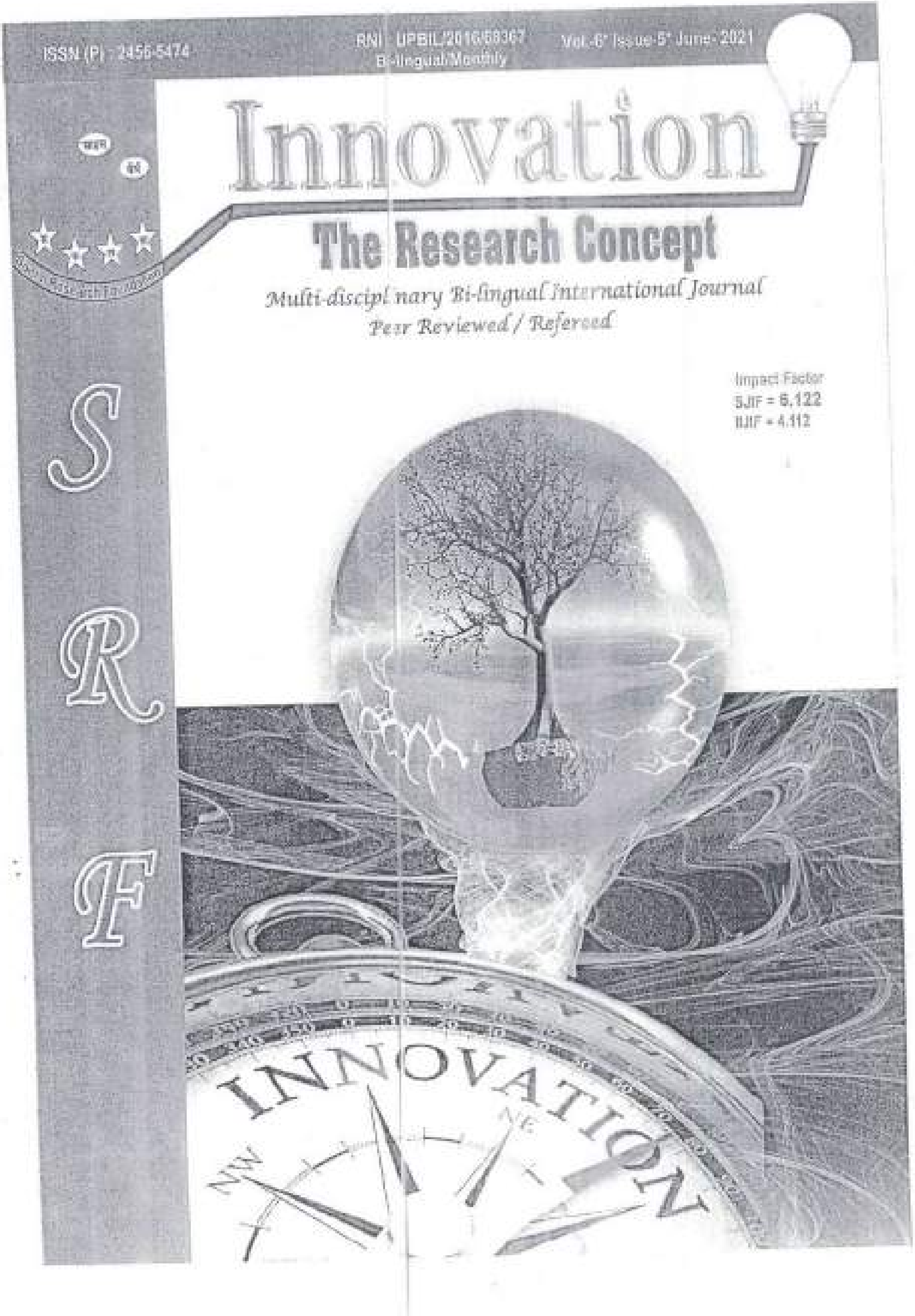

Publication Ethics

The publication ethics of journal Innovation: The Research Concept follows the guidelines of COPE (Committee on Publication Ethics). The process of paper publication is clearly mentioned on our website http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#2. Each and every paper follows the strict

S.no	LIST	Page No
22	**A Study of Phases of the Recruitment and Selection** Jaya Singh, Ayodhya, Uttar Pradesh, India	E-107 to E-108
23	**Health Problem Related to Environmental Issues** Sushmita Upadhyay, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India	E-109 to E-112
24	**Nissim Ezekiel's The Railway Clerk : Escapism Amidst Hardship** Vandana Dubey, Jaunpur, Uttar Pradesh, India	E-113 to E-116
1	शोधोपकरणानि तेषां प्रयोगश्च कुलदीपसिंह, जयपुरम् राजस्थानम् भारतम्	H-01 to H-03
2	ए.ए. अल्तेकर का कला संसार नमिता त्यागी, दयालबाग, आगरा, भारत	H-04 to H-08
3	नाशक कीट प्रबंधन बृजमोहन मीणा, दौसा, राजस्थान, भारत	H-09 to H-14
4	मतदान व्यवहार के अध्ययन के राजनीतिक एवं निर्धारक तत्व वीना राय एवम राखी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत	H-15 to H-18
5	नरसिंहपुर जिले में जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कीर्ति रजक, जबलपुर, म.प्र., भारत	H-19 to H-22
6	समकालीन हिंदी–उर्दू नाटकों के विकास में एस. एम. अजहर आलम की भूमिका इबरार खान, नदिया, पश्चिम बंगाल, भारत	H-23 to H-26
7	महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह अनुपमा दीक्षित, सीकर, राजस्थान, भारत	H-27 to H-31
8	राज्यों की ध्रुवीकृत सम्प्रभुता की नवोत्तर संकल्पना मनमीत सोनी, चूरू, राजस्थान, भारत	H-32 to H-39
9	भारत में नगरीय समाज एक विश्लेषण जितेन्द्र कुमार अहिरवाल, रायसेन, मध्य प्रदेश, भारत	H-40 to H-43
10	सागर नगर के शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन अभिषेक कुमार प्रजापति, अम्बुज कुमार, सागर, म.प्र., भारत	H-44 to H-50
11	भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम इन्द्रेश कुमार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश भारत	H-51 to H-55
12	अलवर जिले के औद्योगिक विकास में ऊर्जा उपभोग प्रतिरूप : एक भौगोलिक विश्लेषण अमित कुमार सिंह एवम धर्मेन्द्र सिंह चौहान, जयपुर, राजस्थान, भारत	H-56 to H-61
13	कविवर सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के विविध रूप गुरमीत सिंह एवम हरकेश बैरवा, बून्दी, राजस्थान, भारत	H-62 to H-65
14	पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन अरविन्द कुमार चौधरी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत	H-66 to H-69
15	भारत मे गिरता हुआ लिंगानुपात : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन दयाशंकर सिंह यादव, चन्दौली, उत्तर प्रदेश, भारत	H-70 to H-73
16	मन्नू भंडारी के 'आपका बंटी' उपन्यास में चित्रित समाज एवं स्त्री जीवन अनूषा निल्मिणी सल्वतुर, श्री लंका	H-74 to H-78
17	सम्राट अशोक की धम्म नीति सागर भूषण सेनापति, कटिहार बिहार, भारत	H-79 to H-85
18	मध्य अलकनन्दा बेसिन में पर्यावरण का बदलता स्वरूप किरन त्रिपाठी एवं मंजू भंडारी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, भारत	H-86 to H-92
19	लोकतान्त्रात्मक शासन प्रणाली और महिला प्रतिनिधित्व शालिनी गुप्ता, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत	H-93 to H-97
20	शेखावाटी भित्ति चित्र और उनका संरक्षण सुमित मेहता, सीकर, राजस्थान, भारत	H-98 to H-100
21	भारतीय नवजागरण, गुरूघासीदास और सतनाम– आन्दोलन फुलसो राजेश पटेल, राजनांदगॉव, श्रुति गावस्कर, बिलासपुर एवं आई. आर. सोनवानी, राजनांदगॉव, (छ.ग.) भारत	H-101 to H-104
22	पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान लाला राम मीना, दौसा, राजस्थान, भारत	H-105 to H-107
23	स्वास्थ्य एवम् अध्यात्म की कुंजी योग (महामारी को दृष्टिगत रखते हुये) रचना त्रिवेदी, उन्नाव, उ0प्र0, भारत	H-108 to H-110

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

भारतीय नवजागरण, गुरूघासीदास और सतनाम–आन्दोलन

Indian Renaissance, Guru Ghasidas and Satnam - Movement

Paper Submission: 10/06/2021, Date of Acceptance: 22/06/2021, Date of Publication: 23/06/2021

आई. आर. सोनवानी
प्राचार्य,
शासकीय रानी अंवन्ति बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, राजनांदगांव, (छ.ग.) भारत

फुलसो राजेश पटेल
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव, (छ.ग.), भारत

श्रुति गावस्कर
शोध छात्रा,
इतिहास विभाग,
सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

सारांश

भारत के नवजागरण विशेषकर स्वाधीनता आन्दोलन में यहाँ के प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय वर्ग के लोगों का अहम भूमिका रही है। राजा, महाराजा, कृषकों, मजदूरों, सन्तों, महात्माओं का स्मरणीय योगदान रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में भारत का कोना–कोना स्वाधीनता आन्दोलन का केन्द्र बन गये थे। छत्तीसगढ़ अंचल इससे अछुता नही था। इस अंचल में नवजागरण का सूत्रपात करने वाला और स्वाधीनता का प्रेरक शक्ति सन्त गुरूघासीदास थे। उन्होंने सन् 1820 से 1830 तक सतनाम आन्दोलन बड़ी तीव्रता से संचालित कर पतनावस्था से लोगों को उन्मुक्त किया था।

वस्तुतः सतनाम आन्दोलन आरम्भिक अवस्था से महज एक सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति ही नहीं थी बल्कि यह सुधारवादी, परिवर्तनवादी जनतंत्रवादी, मानवतावादी और राष्ट्रवादी आन्दोलन था। सतनाम आन्दोलन में क्रांतिकारी सुधारवाद के लक्षण पाये जाते है जिसका जरूरत नवजागरण, भारत की आजादी और भारतीय लोकतंत्र के निमित्त वांछनीय थी।

गुरूघासीदास धार्मिक, अन्धविश्वासों, कर्मकाण्डों, जाति भेद, अस्पृश्यता, तमाम कुप्रथाओं शोषण–दमन तथा सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय अत्याचार जुल्म आदि के खिलाफ खुल्म–खुल्ला विद्रोह कर नवजागरण की किरणों को जन–जन तक पहुँचाया। उन्होंने साम्राज्यवादी और सामंतवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार कर जनतांत्रिक सोच को लोगों में बढ़ाया। फलस्वरूप पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जनमानस में साहस का संचार हुआ और भारतीय राष्ट्रीयता को सबंल मिला यही वजह है कि अंचल में आजादी के आन्दोलन के प्रत्येक मोर्चे पर सफलता मिली। आगे चलकर गांधी जी ने सतनाम आन्दोलन के विचार धारा से प्रभावित होकर सत्याग्रह आन्दोलन का बुनियादी आधार बनाया था।

People of every religion, caste, community class have played an important role in the renaissance of India, especially in the freedom movement. There has been a memorable contribution of kings, maharajas, farmers, laborers, saints, Mahatmas. During the freedom movement, every nook and corner of India had become the center of the freedom movement. Chhattisgarh region was not untouched by this. In this region, the founder of the renaissance and the inspiration of Independence was the Shakti saint Guru Ghasidas. From 1820 to 1830, he freed the people from the decline by conducting the Satnam movement with great intensity.

In fact, the Satnam movement was not only a social and religious revolution from the initial stage, but it was a reformist, revolutionary democratic, humanist and nationalist movement. The characteristics of revolutionary reformism are found in the Satnam movement, which was needed for the sake of renaissance, India's independence and Indian democracy.

Guru Ghasidas openly revolted against religious, superstitions, rituals, caste discrimination, untouchability, all kinds of evil practices, exploitation-oppression and all kinds of social injustice, atrocities, atrocities etc. and brought the rays of renaissance to the masses. He raised democratic thinking among the people by attacking the imperialist and feudal system. As a result, courage was infused in the public to break the shackles of independence and Indian nationalism was strengthened, which is why the freedom movement in the region got success on every front. Later on, Gandhiji, influenced by the ideology of the Satnam movement, made the basic basis of the Satyagraha movement.

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

मुख्य शब्द: गुरुघासीदास धार्मिक, अन्धविश्वासों, कर्मकाण्डों, जाति भेद, अस्पृश्यता।
Guru Ghasidas Religious, Superstitions, Rituals, Caste Discrimination, Untouchability.

प्रस्तावना

पंथ का इतिहास एवं इसके सांस्कृतिक उपादान, उत्पत्ति काल से ही (सन् 1557) सुधारवादी, जनतंत्रवादी और राष्ट्रवादी रहा है। भारतीय संस्कृति के संपोषण और संवर्धन में भी सतनामी परम्परा की उल्लेखनीय भूमिका रही है. मध्यकालीन सतनाम–आन्दोलन, भक्ति आन्दोलन की एक शाखा बनकर प्रारम्भ हुआ था।[1] यह आन्दोलन सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति ही नही बल्कि मानवतावादी, परिवर्तनकारी, जनवादी और राष्ट्रवादी बहुआयामी आंदोलन था।[2] इसकी संपुष्टि मुगलकालीन सन् 1672 के सतनामी विद्रोह से होती है। मुगलकालीन साम्राज्यवाद और धर्मान्धता के विरुद्ध इस संघर्ष में हजारों की संख्या में सतनाम – पंथ के अनुयायी बलिदान हो गये जो बचे वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय या फिर जीवन–यापन के उद्देश्य से भारत के अन्य क्षेत्रों में यथा – उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पहुंचकर बस गये। कालान्तर में बंगाल और आसाम में भी इस सम्प्रदाय का विस्तार हुआ। यह समय सतनाम आन्दोलन का प्रारम्भिक काल था।[3]

अध्ययन का उद्देश्य

भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यही कारण है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए– प्रेरणा–स्त्रोत बना हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास भी समूचे विश्व में अपने अनुपम विलक्षणता के कारण एक अद्वितीय मिशाल के रूप में कायम है जो सबको स्वीकार्य है।

भारत का नव जागरण हो या स्वतंत्रता आन्दोलन इस दिशा में किसी भी व्यक्ति समाज या वर्ग का अवदान राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किये बिना नही रह सकता। इसलिए संकुचित नजरिये से नही विराट दृष्टिकोण से मूल्यांकित कर उनके महत्व को स्थापित करना लाजमि होगा। इस संदर्भ में सन्त गुरुघासी दास के कार्यो एवं उनके द्वारा संचालित सतनाम आन्दोलन को रेखांकित कर राष्ट्रीय इतिहास में जोड़ना या राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थापित करना प्रासंगिक है, जो इस शोध–पत्र का मूल उद्देश्य है।

विषय विस्तार

सतनाम–आन्दोलन का द्वितीय काल बाबा गुरुघासीदास जी के आविर्भाव काल से प्रारंभ होता है। बाबा गुरुघासीदास जी का युग पराधीनता और सांस्कृतिक पराभव का काल था। सांस्कृतिक गौरव की जड़े हिल चुकी थी, पाश्चात्य संस्कृतिक की भूल–भूलैया में लोग अपनी संस्कृति के आदर्शों और जीवन मूल्यों को खो चुके थे। सशक्त वर्णवाद, अपरिवर्तनशील जाति व्यवस्था और तरह–तरह की औचित्यविहिन परम्पराओं एवं मान्यताओं के कारण भारतीय समाज की गत्यात्मक शक्ति क्षीण हो चुकी थी।[4]सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश मात्र उपदेश बनकर रह गया था। 'सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वसन्तुनिरामया" जैसे कल्याणकारी संदेश अप्रासंगिक हो चुके थे। "वसुधैव कुटुम्बकम" की अवधारणा स्थापित करने वाले भारत की प्राचीन प्राण शक्ति सुषुप्त हो चुकी थी तथा जीवन और सृजन का वृहत्तर विचार समाप्त हो चुका था। उन्मुक्त विवेक आदि चिंतन का अभाव था तथा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में विराम लग चुका था।[5]

प्रायः इतिहासकार भारतीय नवजागरण के तौर तरीके, उसकी समग्रता और उसमें छिपे अंतर्भाव को समझे बिना मोटे तौर पर राजा राममोहनराय के समय से भारतीय पुर्नजागरण की शुरुवात मानते हैं, बाबा गुरुघासीदास जी के सुधार आंदोलनों को राष्ट्रीय पुर्नजागरण की श्रृंखला में स्थापित करने में परहेज करते हैं। गुरुघासीदास जी भारत के सांस्कृतिक नवजागरण के गुरु थे। गुरुजी राजाराम मोहन राय के पहले ही सतनाम पंथ की स्थापना कर सन् 1820 में सतनाम आंदोलन चलाये थे। फलतः भारतीय नवजागरण पल्लवित हुआ गुरुघासीदास जी का नवजागरण भारतीय लोक परम्परा से उद्भूत था, जबकि राजा राममोहन राय का नवजागरण पश्चिमी परम्परा से अनुस्यूत था। डॉ. हीरालाल शुक्ल ने कहा कि सन्त गुरु घासीदास भारत में नवजागरण की रश्मि फैलाई। उन्होंने नवजागरण की आत्मा को समाज तक पहुँचाया।[6]

भारतीय नवजागरण की समग्र व्याख्या कर विराट दृष्टि से भारतीय नवजागरण के आयामों में विशेष कर राष्ट्रीय पटल में गुरुघासीदास जी के सुधार कार्यों को मूल्यांकित करके उसे स्थापित करना प्रासंगिक होगा अन्यथा नवजागरण की ऐतिहासिक विकास प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण अंग को नजर अंदाज करना या दूसरे अर्थो में नवजागरण की गम्भीरता और विशिष्टताओं को सही मायने में अधूरा समझने के समान होगा। यदि समाज के निचले स्तर पर होने वाले खलबलियों, बदलाओं तथा सुधार के प्रयत्नों को इतिहास का विषय बनाया जाय तब कहीं इतिहास की व्यापकता और समग्रता लगभग पूरी हो पाती है।[7] किसी देश या प्रदेश के सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलन को नवजागरण कहा जाता है, उसमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न शामिल रहता है। निम्नवर्गीय लोगों और स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास, नवजागरण का अंग कहलाता है। धार्मिक सुधार, अंध–विश्वासों के विरुद्ध प्रचार, नवजागरण के अन्तर्गत शामिल रहता है यदि नवजागरण समाज में मौलिक परिवर्तन का ध्येय लेकर बढ़ता है तो वह स्वाधीनता आन्दोलन की प्रेरक शक्ति बनता है।[8] हां इतना जरूर है कि कोई भी नवजागरण हो, उसका जातीय स्वरूप अवश्य रहेगा। जातीय जागरण को ही अक्सर नवजागरण कहा जाता है।[9] इस प्रकार हर नवजागरण जातीय संगठन और विकास में सहायक होता है और यही राष्ट्रीय चेतना और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में कोई भी जातीय जागरण या प्रदेशगत स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किये बिना नही रह सकता[10] भले ही किसी का प्रभाव सीमित अथवा व्यापक हो यह अलग बात है बंगाल के सन्यासी विद्रोह

का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित था, पर उसके राष्ट्रीय महत्व को अस्वीकार करना गलत होगा। सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव अधिक था, पर उसका मुख्य क्षेत्र हिन्दी भाषीय प्रदेश था। अतः इसके जातीय स्वरूप को नकारना गलत होगा।[11] भारत की भक्ति आंदोलन बहुराष्ट्रीय आन्दोलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। भक्ति आन्दोलन में निम्न वर्ग के लोगों मुसलमानों और स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसलिए उस आंदोलन ने सीमित नवजागरण का नही व्यापक लोकजागरण का रूप लिया।[12] सामाजिक, विषमता और साम्प्रदायिक भेदभाव दूर करने में उसकी भूमिका युगान्तकारी थी। भक्ति आन्दोलन जैसे लोकजागरण बना वैसे ही देश के एक विशाल भू–भाग में सन् 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जन आन्दोलन बना। इसी तरह सतनाम आंदोलन का वृहत्तर राष्ट्रीय विचार, नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरक शक्ति बनकर सत्याग्रह आंदोलन में अन्तर्वेशित हो गया और भारत की आजादी तक गतिशील रहा इस प्रकार बाबा गुरुघासीदास जी के सामाजिक धार्मिक सुधारकार्य तथा राजनैतिक विचार उनके द्वारा संचालित सतनाम आंदोलन के सिद्धान्त , कार्यक्रम, उद्देश्य फलस्वरूप सामाजिक जागरण भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से प्रभावकारी है।[13] 18दिसम्बर 1756 ईसवी में भारतीय

नवजागरण के युग पुरुष बाबा गुरुघासीदास जी का जन्म हुआ। इसके छः माह पश्चात 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजो ने बंगाल में नई अलमदारी कायम की फिर क्रमशः ब्रिटिश साम्राज्यवाद रूपी रथ चक्र भारत के अन्य प्रांतो में घूमता गया। भारतीय नरेश इस रथ चक्र के नीचे धराशायी होते गये और अंग्रेज भारत के हुकूमदार बन गये। वस्तुतः एक तरफ ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई और दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ता के प्रतिरोध में नवजागरण की हलचल और उबाल आने से विद्रोह की ज्वालामुखी भिन्न–भिन्न रूपों में फूटने लगी। गुरु जी के सतनाम आन्दोलन में प्रसिद्ध कवि शैली के समान जनतांत्रिक क्रान्ति का विचार मिलता है। इस मायने में वे जनवादी आन्दोलन के प्रबल समर्थक थे। गुरुजी के इस आन्दोलन में मार्क्स की क्रान्ति समाजवादी विचार धारा का संप्रेषण है। उनके सतनाम आन्दोलन के सुधार चक्र में सुकरात, एंगेल्स के समान धार्मिक अन्धविश्वासों, कर्मकाण्डों तथा कांट की भांति हर तरह के सामाजिक अन्याय को विरोध दर्शित होता है।

बाबा गुरुघासीदास जी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति के जनक तथा राजनीतिक पहलू में क्रांतिकारी सुधारवाद के हिमायती थे।[14] उनके द्वारा प्रणीत सतनाम आंदोलन, पुरोहितवाद के खिलाफ समझौता विहिन संघर्ष और लोकाधिकार के प्रति चेतनामूलक मुहिम था।[15] बाबाजी द्वारा प्रतिपादित सतनाम–दर्शन विवेकवादी दर्शन था, उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कर्मकाण्डों, जातिवाद, ऊँच–नीच, छुआ–छूत और एकांगी उन्नति के विरुद्ध लोक मानस को उन्मुक्त कर सर्वोन्नति और समग्र जागरण के उदान्त विचार को विकसित किया। पुरोहित वाद और सामंतवाद के बने हुए ढांचे को ध्वस्त कर, लोकतांत्रिक सोच को बढ़ाना तथा सार्वभौमिक उन्नति के आयामों को स्थापित करना सतनाम आन्दोलन का एक लक्ष्य था।[16] वे अंग्रेजी राज के संदर्भ में साम्राज्यवाद, भारत की मौजूदा सामंती संरचना, तदानुकूल राजनीतिक हालात और अंग्रेजो के मौसेरे–भाई, समझे जाने वाला शासक वर्ग (सामंतवर्ग) के खिलाफ खुल्लम–खुल्ला विद्रोह कर चुके थे। वास्तव में उनके द्वारा संचालित सतनाम आन्दोलन विकासशील और जनवादी आन्दोलन था परन्तु सामन्तवादी समीक्षक, साम्राज्यवादी विरोधी आन्दोलन को आगे बढ़ाने की जरूरतों से मेल नही खाते, इस प्रकार की दलील देते हुए इसे केवल सामाजिक विद्रोह के खाते में डाल देते हैं,[17] जबकि वास्तव में सतनाम आन्दोलन सुधारवादी आन्दोलन था और गुरुघासीदास जी क्रांतिकारी सुधारवाद के प्रबल समर्थक थे। यहां पर सुधारवाद को समझना उचित होगा, सुधारवाद के दो पहलू होते है– एक औपनिवेशिक सुधारवाद और दूसरा क्रांतिकारी सुधारवाद, औपनिवेशिक सुधारवाद उपनिवेशवाद के पक्ष मे चलता है, जबकि क्रांतिकारी सुधारवाद, जनता के जनतांत्रिक पक्ष का समर्थन करता है।[18] औपनिवेशक सुधारवाद दृष्टिविहिन होता है, यह सारगर्भित राष्ट्रीय परम्पराओं को कुचलते हुए आगे बढ़ता है, और हमेशा विशिष्टवर्ग को संतुष्ट करता है।[19] क्रांतिकारी सुधारवाद दृष्टिसम्पन्न होता है, यह राष्ट्रीय परम्पराओं से विकासशील संबंध रखता है, और सर्वहारा वर्ग के हितों का रक्षण करते हुए बढ़ता है।[20] इस प्रकार औपनिवेशक सुधारवाद मनुष्य को परजीवी बनाता है और एकांगी नवजागरण लाता है, जबकि क्रांतिकारी सुधारवाद लोगों को आत्मसचेत करते हुये समग्र नवजागरण लाता है।[21] इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि बाबा गुरुघासीदास के विवेकवादी दर्शन और सतनाम आंदोलन की टकराहट से जनमानस में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना का प्रस्फुटन हुआ जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय स्वतंत्रता के युग में राष्ट्रवादी आन्दोलनों में हुई, उनके क्रांतिकारी सुधार आन्दोलनों और नवजागरण के प्रयत्नों से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषक नेता वीर नारायण सिंह ने सन् 1857 में अंग्रेजो के दकियानुसी, कल्पनाहीन, कुशासन के खिलाफ विद्रोह कर आत्मबलिदान दिया। भारत के अन्य भागों मे भी इसी तरह की बहुत सी घटनाएँ घटी यद्यपि ये प्रयास प्रारम्भिक अवस्था में विफल हो गये। इस तरह बाबा गुरु घासीदास ने भारतीय राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय विचार को अपने क्रांतिकारी सुधारवादी आंदोलनों के द्वारा जनता तक फैलाया जिसकी विशेषताएँ बाद के राष्ट्रीय आंदोलन तथा जनतांत्रिक सुधारों के रूप में परिलक्षित हुईं। सन् 1850 ई. के आस–पास गुरुघासीदास सतलोक वासी हो गये इसके पश्चात उनके पुत्र गुरु बालकदास जी उत्तराधिकारी हुए। वे इस समाज के लौहपुरुष थे, गुरु बालकदास जी ने सतनामी समाज का राजा होने की सनद ब्रिटिश सरकार से प्राप्त की थी। यह सनद अंग्रेजी राज्य के प्रति भक्ति रखने की बदौलत नही बल्कि इसलिए प्राप्त हुई थी की इस समाज के वे राजा समान थे। अतः इस अधिकार को वैधता प्रदान करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से मांग रखते हुए संघर्ष किया था।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

गुरू बालकदास सतनाम पंथ के समस्त अनुयायियों को प्रजातुल्य समझते थे। उनकी सुरक्षा, समाज का संचालन, प्रजा का कल्याण करना अपना कर्तव्य मानते थे। गुरू बालकदास ने समाज को संगठित, शक्तिशाली और जनता को चरित्रवान बनाने के लिए अखाड़ा–प्रथा की शुरूवात की थी। इससे लोगों में अनुशासन, आत्मबल, उच्च चरित्र और देश भक्ति का विकास हुआ।[22] अखाड़ा पद्धति बाद में राष्ट्रीय सेवादल के आचार संहिता के बतौर काम आई। उन्होंने सतनाम आंदोलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सतनाम आंदोलन के राष्ट्रवादी जनतांत्रिक प्रभावी, कार्यक्रमों से एक तरफ भारतीय समाज की पुरातनवादी व्यवस्था को चुनौती मिली, वही दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की चूले हिलने लगी। फलतः बालक दास जी को अंग्रेजों और कतिपय कट्टरपंथियों के संयुक्त षडयंत्र का शिकार होना पड़ा। सन् 1860 के आसपास अंग्रेजों ने उनकी हत्या करवा दी।[23] स्वतंत्रता संघर्ष के महाअनुष्ठान में सोनाखान के नर केसरी नारायण सिंह के बाद प्रदेश के बलिदान होने वाले, वे दूसरे वीर पुरूष थे। इस घटना के साथ ही सतनाम आन्दोलन का द्वितीय काल समाप्त होता है। कालान्तर में जब गुरू अगमदास उत्तराधिकारी हुए तब सतनाम आन्दोलन उनके नेतृत्व में सामाजिकों और अंचल के जन सहयोग से पुनः गतिमान हो उठा। गुरू अगमदास अपने समय के लोक नायक माने जाते है। उन्हें सतनाम आन्दोलन को संचालित करने में काफी जनसमर्थन और सहयोग मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कार्यक्रम के अनुसार देश में उदारवादी आन्दोलन चला, तब इस समय गो वंश की रक्षा और गो हत्या रोकने के मुद्दों को सतनाम आन्दोलन का नया राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित कर गो हत्या बंद आन्दोलन सन् 1914 से 1924 ई. तक सफलता पूर्वक चलाया।[24] सन् 1920 में भारत की राजनीतिक क्षितिज पर गांधी जी का आविर्भाव हुआ। फलतः सतनाम आन्दोलन गांधी युग में गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन में अन्तर्वेशित हो गया और भारत की आजादी तक अपने मूल सिद्धान्तों को सहेजे हुए क्रियाशीलता बनाये रखा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में गुरूघासी दास और उनके द्वारा प्रणीत सतनाम–आन्दोलन के पृष्ठभूमि को शोध परक अध्ययन कर तथ्यात्मक और प्रमाणिक तौर पर प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है।

छत्तीसगढ़ की पावन भूमि एवं जनमानस में गुरूघासीदास जी के सतनाम सिद्धान्त, शिक्षाएँ उनके उद्देश्य कार्य रचा–बसा हुआ है तथा उनके आदर्शो को केन्द्रीय मूल्य के रूप में पहचान मिली है। गुरूजी के व्यक्तित्व एवं आदर्श सामाजिक समरसता सौहार्द, भाई–चारे और मानवता की दिशा में हमेशा के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय परिदृश्य में सन्त गुरू घासीदास के योगदान को समुचित स्थान मिलने से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा तथा देश का इतिहास समृद्ध होगा। इतना ही नही राष्ट्रीय धारा में स्थान मिलने से समाहित होने से भारतीय राष्ट्रीयता को सबल बनाने के लिए एक नया आधार मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रकाश बुद्ध– हरियाणा का इतिहास, एक सर्वेक्षण–पृ 51*
2. *उक्त–पृ 52*
3. *डिण्डे, धनाराम–सतनामी इतिहास और गुरूघासीदास– पृ 17*
4. *देसाई.एआर.– भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि –पृ 193*
5. *श्रीवास्तव, डी.पी.– भारत के राजनीतिक पुनर्जागरण पर धार्मिक आंदोलन का प्रभाव–पृ 06*
6. *शुक्ल डॉ. हीरालाल – गुरूघासीदास संघर्ष, समन्वय और सिद्धान्त –पृ 184–188*
7. *सुमित, सरकार– आधुनिक भारत –पृ 61*
8. *शर्मा, रामविलास – स्वाधीनता संग्राम के बदलते परिप्रेक्ष्य – पृ 121*
9. *पूर्वोक्त– पृ 121*
10. *पूर्वोक्त– पृ 122*
11. *पूर्वोक्त –पृ 122*
12. *पूर्वोक्त – पृ 123*
13. *ठाकुर, हरि– युग पुरूष गुरूघासीदास– पृ 13*
14. *कनौजे, मेघनाथ – दिव्य ज्ञान के ज्योतिपुरूष गुरूघासीदास – पृ 05*
15. *कैप्टन, जे. फोरसिथ – दि हाइलैण्ड आफ सेन्ट्रल इंडिया – पृ 328*
16. *अमीन शाहिद, पाण्डे ज्ञानेन्द्र– निम्नवर्गीय प्रसंग –भाग 1–पृ 144*
17. *शम्भूनाथ – दूसरे नवजागरण की ओर –पृ 09*
18. *पूर्वोक्त– पृ 09*
19. *पूर्वोक्त– पृ 09*
20. *पूर्वोक्त–पृ 09*
21. *ठाकुर, हरि– युग पुरूष गुरूघासीदास–पृ 14*
22. *सोनी जे आर – सतनाम के अनुयायी –पृ 13*
23. *रसेल एण्ड हीरालाल– ट्राइब्स एण्ड कास्टस आफ दी जनरल प्रॉविंसेस आफ इंडिया –पृ 310*
24. *डिण्डे, धनाराम– सम्पादक, सत्यदर्शन स्मारिका –पृ 08*